



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]  
No. 122]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2007/फाल्गुन 29, 1928  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2007/PHALGUNA 29, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

सा.का.नि. 213 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 है ।  
(2) ये नियम 3 के उप-नियम (1) के द्वितीय परंतुक और नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (i) के परंतुक के सिवाय, जो 1-4-2007 से प्रभावी होंगे, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'तल चिन्ह प्राप्तार्क' से ऊपर समग्र श्रेणीकरण के लिए न्यूनतम सांख्यिकीय भार अभिप्रेत है, जिससे किसी अधिकारी को अगली उच्चतर श्रेणी में, यथास्थिति, प्रोन्नति या पैनल में रखे जाने के लिए उपयुक्त समझा जाएगा;

- (ख) 'काडर' और 'काडर पदों' के क्रमशः वहीं अर्थ हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उनके हैं ;
- (ग) 'विभागीय परीक्षा' से ऐसी परीक्षा अभिप्रेत है जो राज्य के काडर को आबंटित सेवा के या प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात सदस्यों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ;
- (घ) 'सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया जाता है ;
- (ङ) 'श्रेणी वेतनमान' से सेवा के किसी सदस्य द्वारा से उस श्रेणी में जिसमें उसे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता है, प्राप्त किया गया मूल वेतनमान अभिप्रेत है ;
- (च) 'धारणाधिकार' से नियमित आधार पर या तो किसी अवधि के अवसान पर या अवधियों की अनुपस्थिति में ठीक पूर्व धारण करने के लिए, जिसके अंतर्गत ऐसा कालावधि पद है, जिस पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जिस पर वह परीक्षा पर नहीं है, सेवा के किसी सदस्य का हक अभिप्रेत है ;
- (छ) 'सेवा का सदस्य' से भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ज) 'गैर-राज्य सिविल सेवा' का वहीं अर्थ है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (2) में उसका है ;
- (झ) 'चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी' से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (2) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (अ) 'स्थानापन्न' से किसी ऐसे पद के कर्तव्यों का पालन करने वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर सेवा के किसी अन्य सदस्य का धारणाधिकार है और इसके अंतर्गत किसी रिक्त पद पर, जिस पर सेवा के किसी अन्य सदस्य का धारणाधिकार नहीं है, स्थानापन्न हैसियत में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी है ;
- (ट) 'वैयक्तिक वेतन' से,-
- (क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अधिष्ठायी वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक कटौती के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायी पद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि से बचाने के लिए ; या
- (ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में, सेवा के किसी सदस्य को अनुदत्त अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है ;
- (ठ) 'प्रोन्नत अधिकारी' से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसार किसी राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ड) 'प्रोन्नति' से उस श्रेणी से जिसमें वह सुसंगत समय पर कार्यरत है, अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है ;
- (ढ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

- (ण) 'सेवा' से भारतीय प्रशासनिक सेवा अभिप्रेत है ;
- (त) 'राज्य' से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और इसमें सब राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ;
- (थ) 'राज्य काडर और संयुक्त काडर' के क्रमशः वहीं अर्थ हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उनके हैं ;
- (द) 'राज्य सिविल सेवा' का वहीं अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है ;
- (ध) किसी संयुक्त काडर के संबंध में 'संबंधित राज्य सरकार' से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

टिप्पण 1 :- तल चिह्न प्राप्तों को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा वेनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सरकार द्वारा तल चिह्नों के पुनरीक्षण के भविष्यलक्षी प्रभाव होंगे।

टिप्पण 2 :- श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्नतर श्रेणी में प्रत्यावर्तित किए जाने के योग्य होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक है ;

3. इन श्रेणियों में वेतनमान और नियुक्ति :- (1) सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनमान और वह तारीखें जिससे उक्त वेतनमान प्रभावी समझे जाएंगे, निम्न प्रकार से हैं :-

कनिष्ठ वेतनमान - 8000-275-13500/-रु. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ।

ज्येष्ठ वेतनमान - (i) काल वेतनमान - 10650-325-15850/-रु. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी - 12750-375-16500/-रु. (अकृषिक) (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

(iii) चयन श्रेणी - 15100-400-18300/-रु. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

अतिकाल वेतनमान - (क) 18400-500-22400/-रु. (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी) ;

अतिकाल वेतनमान से ऊपर - (i) 22400-525-24500/-रु.

(ii) 26000/-रु. (नियत)

(iii) 30000/-रु. (नियत) (केवल भारत सरकार के मंत्रिमंडल अधिक के पद के लिए) (1 जनवरी, 1996 से प्रभावी)

टिप्पण - अतिकाल वेतनमान और उससे ऊपर के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बाबत मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा :

परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उसकी सेवा के 9 वर्ष पूरा होने पर, चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर और अतिकाल वेतनमान में सेवा के 16 वर्ष पूरा होने पर नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

परंतु यह और कि सेवा के किसी सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में यथाविहित चरण III मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा।

**टिप्पण 1** . इन नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों और सोलह वर्षों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1987 के नियम 3 के अधीन उसको आबंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा।

**टिप्पण 2** . चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से ली गई, समझी गई या आगे अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी को, जो लोकहित में हैं और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अनुज्ञेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि सेवा का कोई सदस्य, विद्यमान वेतनमान में उस तारीख तक वेतन लेने का विकल्प दे सकेगा जिसको वह विद्यमान वेतनमान में अपनी अगली या कोई पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि अर्जित करता है यह तब जब वह पद रिक्त कर देता है या उस श्रेणी में वेतन लेना बंद कर देता है। विकल्प का ऐसे आदेशों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं ;

**स्पष्टीकरण 1** . इस नियम के परंतुक के अधीन विद्यमान वेतनमान धारण करने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा।

**स्पष्टीकरण 2** . उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुज्ञात किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 3** . जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतनमान के विनियमन के प्रयोजन के लिए किसी नियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में, विद्यमान पद धारण करने के लिए इस नियम के परंतुक के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, वहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान वेतनमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो।

2(i). भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन श्रेणी और उस श्रेणी से ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति उस कसौटी के अनुसार गुणागुणा के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता को सम्मकतः ध्यान में रखते हुए, विहित की जाए ;

परंतु सेवा के किसी सदस्य को, अतिकाल वेतनमान में यथाविहित चरण iv आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा ;

(ii) चयन श्रेणी और अपर की श्रेणी के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उस श्रेणी में उपलब्ध शक्तियों के अध्यक्षीन में रहते हुए, की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति राज्य काडरों या संयुक्त काडर प्राधिकारियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध शक्तियों की संख्या के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रतिनिर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी सहमति देगी और यदि केन्द्रीय सरकार उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर सहमति नहीं देती है तो शक्तियों की उपलब्धता पर सहमति दी गई समझी जाएगी । इस खंड में यथानिर्दिष्ट प्रकट करने वाली स्थिति को उस समय जब यह इन श्रेणियों में प्रोन्नति में विचार करने के लिए बैठक करती है, समीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी ।

(iv) सेवा का कोई सदस्य, इन श्रेणियों में नियुक्ति पर केवल चयन श्रेणी और ऊपर की श्रेणी में वेतन लेने का हकदार होगा ।

3क. पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का नियतन - सेवा के किसी सदस्य का आरंभिक वेतन, जिसके लिए वह इन नियमों के अनुसार विकल्प देता है या विकल्प दिया गया समझा जाता है, 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् की तारीख से ही पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होगा । जो स्थायी पद में उसके अधिष्ठायी वेतन के संबंध में उस तारीख से पृथक् रूप से पुनः नियतन किया जाएगा जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या उसमें धारणाधिकार धारित किया होता तो उसे निलंबित नहीं किया गया होता और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके और उसके वेतन के संबंध में उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद निम्नलिखित रीति में धारित किया जाएगा अर्थात् :-

(अ) सेवा के सभी सदस्यों की दशाओं में, -

(i) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन के चालीस प्रतिशत की राशि सेवा के सदस्य की 'विद्यमान परिलब्धियों' में जोड़ दी जाएगी ;

(ii) विद्यमान परिलब्धियों में इस प्रकार वृद्धि करने के पश्चात् वेतन को तत्पश्चात् संगणित की गई राशि से अधिक अगले प्रक्रम पर पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाएगा :

परंतु यह कि

(क) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम इस प्रकार प्राप्त वेतनमान से अधिक है तो वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा ।

(ख) यदि इस प्रकार प्राप्त रकम पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक है तो वेतन को उसी वेतनमान के वेतन पर नियत किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां वेतन के नियतन में, किसी विद्यमान वेतनमान में जैसा आनुक्रमिक प्रक्रमों से अधिक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य का वेतन एकीकृत कर दिया जाता है अर्थात् पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम पर नियत हो जाता है वहां, सेवा के ऐसे सदस्य के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का, जो विद्यमान वेतन में पहले जैसा आनुक्रमिक प्रक्रमों के परे वेतन पा रहा है, अगले प्रक्रम पर ले जाया जाएगा जहां ऐसा एकीकरण निम्नलिखित रीति में पुनरीक्षित वेतन वृद्धियां अनुदत्त करके होता है अर्थात् :-

(क) विद्यमान वेतनमान में पांचवें से आठवें प्रक्रम तक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए, एक वेतन वृद्धि द्वारा ;

(ख) विद्यमान वेतनमान में 9वें से 12वें प्रक्रम तक वेतन वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए यदि 8वें प्रक्रम के परे एकीकरण होता है, दो वेतनवृद्धि द्वारा ;

(ग) विद्यमान वेतनमान में 13वें प्रक्रम से 16वें प्रक्रम तक एक वेतन पाने वाले सेवा के किसी सदस्य के लिए यदि 12वें प्रक्रम के परे एकीकरण होता है, तीन वेतनवृद्धि द्वारा ;

यदि इस नियम में यथानिर्दिष्ट वेतन को आगे बढ़ाकर सेवा के किसी सदस्य का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में किसी प्रक्रम पर इस प्रकार नियत हो जाती है जो पुनरीक्षित वेतनमान में उस प्रक्रम से उच्चतर है, जिस पर सेवा के किसी सदस्य का वेतन, जो उसी विद्यमान वेतनमान में वेतन पा रहा था, नियत हो जाता है, पश्चात्कथित का वेतन ही उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाएगा जिस तक पूर्वकथित की कमी होती है :

परंतु यह भी की वेतन के नियतन को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा की सेवा का प्रत्येक सदस्य विद्यमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों (जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियों की वृद्धिरुद्ध भी हैं) यदि कोई हो, के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए विद्यमान परिलब्धियों में निम्नलिखित सम्मिलित है ।

(क) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन ;

(ख) मूल अनुक्रमणिका औसत 1510 (1960 = 100) पर अनुज्ञात मूल वेतन का समुचित महंगाई भत्ता ; और

(ग) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन पर अनुज्ञात अंतरिम अनुतोष की पहली और दूसरी किस्त की राशि ; और

(आ) सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम पद्धति के साथ विशेष वेतन संघटक प्राप्त करता है, जैसे प्रोन्नति के लिए वैयक्तिक वेतन, लघु कुटुंब मापमान, केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता आदि, और जिसकी दशा में उसी तत्समान भत्ते के साथ पुनरीक्षित वेतनमान में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या वेतन को उसी दर या किसी विभिन्न दर पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन को खंड (क) के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा और ऐसी दशाओं में सिफारिश की गई नई दर से भत्ता, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा।

टिप्पण - 1 : जहां सेवा के किसी सदस्य की वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 1996 को होती है, वहां उसके पास विद्यमान वेतनमान या पुनरीक्षित वेतनमान वेतनवृद्धि प्राप्त करने का एक विकल्प होगा।

टिप्पण - 2 : जहां सेवा का कोई सदस्य, 1 जनवरी, 1996 को, अखिल भारतीय सेवा (अध्यन छुट्टी) विनियम 1960 के अधीन मंजूर की गई छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी पर ही उस तारीख से जिसका वह कारबार ग्रहण करता है वहां वह पुनरीक्षित वेतनमान वेतन का हकदार हो जाएगा और निलंबनाधीन सेवा के किसी सदस्य की दशा में, वह विद्यमान वेतनमान पर धारित जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा और पुनरीक्षित वेतनमान उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्रवाईयों पर अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

टिप्पण - 3 : जहां यथास्थिति खंड (क) या (ख) के अनुसार यथासंगणित विद्यमान परिलब्धियां सेवा के किसी सदस्य की दशा में पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हो जाते हैं, वहां अंतर को वेतन मान में भावी वेतनवृद्धियों में समामेलित किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

टिप्पण - 4 : जहां, इन नियमों के अधीन वेतन के नियतन में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, जो 1 जनवरी, 1996 से ठीक पूर्व विद्यमान वेतनमान में प्राप्त कर रहा था, उसी कांडर में उससे कनिष्ठ सेवा के अन्य सदस्य से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे कनिष्ठ सदस्य से निम्नतर प्रक्रम पर पुनरीक्षित वेतनमान में नियत हो जाता है, उसके वेतन को कनिष्ठ वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम तक बढ़ाया जाएगा।

टिप्पण - 5 : जहां, सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 1996 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त करता है, जो यथास्थिति, खंड (क) या (ख) के अनुसार यथास्थिति, खंड (क) या (ख) के अनुसार यथासंगणित उसके विद्यमान परिलब्धियों को मिलाकर पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसे आधिक्य के अंतर को, वेतनमान में भावी वृद्धियों के समामेलन किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में सेवा के ऐसे सदस्य को अनुज्ञात किया जाएगा।

टिप्पण - 6 : जहां 1 जनवरी, 1996 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया सेवा का कोई ज्येष्ठ सदस्य अपने कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जात है, वहां सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को उस उच्चतर पद में

उसके कनिष्ठ सदस्य के लिए नियत किए गए वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा और वेतन के बढ़ाए जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, सेवा के कनिष्ठ सदस्य की प्रोन्नति की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

(क) सेवा के कनिष्ठ और ज्येष्ठ सदस्य दोनों उसी कांडर के होंगे और वह पद जिन पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है उसी कांडर में समान होंगे ;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों के पुनरीक्षण पूर्व और पुनरीक्षित वेतनमान, जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे ;

(ग) प्रोन्नति के समय सेवा का ज्येष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो ; और

(घ) विषमता, इस उप नियम के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः होगी भले ही निम्नतर पद में, कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण ज्येष्ठ व्यक्ति से पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, इस नियम के उपबंधों को सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है ।

**टिप्पण 7 :-** उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में, सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन के पुनःनियतन से संबंधित आदेश सुसंगित नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का ज्येष्ठ सदस्य, वेतन के पुनःनियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतन वृद्धि का हकदार होगा ।

**टिप्पण 8 :-** उपनियम (1) के अधीन रहते हुए यदि, इस नियम के अधीन स्थानापन्न पद में नियत वेतन अधिष्ठायी पद पर नियत पद से निम्नतर है, तो पूर्वकथित को अधिष्ठायी वेतन के उपरोक्त प्रक्रम से अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

**टिप्पण 9 :-** सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व हिंदी शिक्षण स्कीम के अधीन हिंदी प्रज्ञा और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त करता है, पुनरीक्षित वेतनमान में आरंभिक वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए जब वैयक्तिक वेतन हिसाब में नहीं लिया जाएगा, तो वह 1 जनवरी, 1996 से ही या उस अवधि के लिए जिसके लिए वह उतना वेतन लेता है जो वह पुनरीक्षित वेतनमान में अपने वेतन के नियतन पर लेता, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने वेतन के नियतन के पश्चात् वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा और ऐसे वैयक्तिक वेतन की मात्रा, उस अवधि के वेतन के नियतन की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर पर संदत्त की जाएगी जिसके लिए सेवा का सदस्य उसे प्राप्त करता ।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजन के लिए “ पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर ” उस प्रक्रम पर या उससे ठीक पश्चात् जिस पर पुनरीक्षित वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन नियत किया जाता है, अनुज्ञेय वेतनवृद्धि की राशि अभिप्रेत है ।

(इ) 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान का नियतन -- जहां, सेवा का कोई सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान के लिए विकल्प देता है, वहां उसके वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान में पश्चात्कथित तारीख से इन नियमों के अधीन नियत किया जाएगा और विद्यमान वेतन में उसके वेतन के इस प्रयोजन के लिए वही वेतन होगा जो इन



शर्तों के अधीन रहते हुए कि मूल वेतन को उन परिलब्धियों की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा जो पश्चात्कथित तारीख को मूल वेतन होगा, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार यथासंगणित विद्यमान परिलब्धियां हैं और जहां सेवा का सदस्य भत्ता प्राप्त करता है, वहां उसका वेतन उन परिलब्धियों से, इस प्रकार संगणित परिलब्धियों से समुचित पुनरीक्षित दरों पर विशेष भत्ते के बराबर राशि की कटौती करने के पश्चात् नियत किया जाएगा।

**4. आरंभिक वेतन का नियतन** - (1) किसी सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति का आरंभिक वेतन, कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा।

परंतु यदि कोई सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति, कोई धारणाधिकार धारण करता है या धारणाधिकार धारण करेगा, यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसे लागू नियमों के अधीन किसी स्थायी पद पर निलंबित नहीं किया जाता है तो उसके आरंभिक वेतन को निम्नलिखित रीति में विनियमित किया जाएगा :-

(क) वह परीक्षा अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन प्राप्त करेगा और यदि यह कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम और भारतीय प्रशासनिक सेवा में पुष्टि पर किया है ;

(ख) यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से पूर्व कोई वर्ग-1 पद धारण कर रहा था तो उसका वेतन उसी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उसका वेतन वर्ग 1 पद पर होता। यदि सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय कनिष्ठ वेतनमान के किसी प्रक्रम पर या उसके निम्नतर प्रक्रम पर होता, यदि सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय कनिष्ठ वेतनमान में कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है और जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस प्रकार नियत वेतन वर्ग - 1 पद में उसके पद से कम है तो उसे आवी वेतनवृद्धि में समामेलित किए जाने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में अंतर को अनुज्ञात किया जाएगा ; और

(ग) यदि वह किसी वर्ग - 1 पद से निम्नतर पद धारण कर रहा था तो उसके वेतन को, निम्नतर पद के संबंध में उस प्रक्रम पर, जिस पर ऐसा वेतन उद्भूत होता है, एक वेतनवृद्धि की उसके वेतन में वृद्धि करके सैद्धांतिक रूप से वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर निश्चित किया जाएगा।

(घ) वह तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में जब तक कोई वेतन वृद्धि अर्जित करना बंद कर देगा तब तक उसकी सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, वह किसी उच्चतर वेतनमान के लिए हकदार नहीं हो जाता है :

परंतु यह और कि वह नियम 7 के अधीन अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करेगा, यदि वह पूर्वगामी उपबंधों में निर्दिष्ट वेतन से किया है।

(2) कनिष्ठ वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, ज्येष्ठकाल वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति पर ऐसे प्रक्रम पर जिस पर ऐसा उद्भूत वेतन (या निम्नतर वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर किसी राशि की यदि वह निम्नतर वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा था) या उच्चतर वेतनमान के न्यूनतम पर इनमें से जो भी अधिक हो, एक वेतनवृद्धि की निम्नतर वेतनमान में उसके वेतन में वृद्धि करने से प्राप्त सैद्धांतिक वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

(3) राज्य सिविल सेवा का अधिकारी की आरंभिक वेतन, यथास्थिति, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी काडर पद पर नियुक्ति पर अनुसूची-1 में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा। वेतन और वेतनवृद्धि फायदे, अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उससे उद्भूत होंगे।

(4) यथास्थिति, सेवा में, चयन द्वारा नियुक्त किए गए या भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी काडर पद पर नियुक्ति पर किसी अधिकारी का आरंभिक वेतन, केन्द्रीय सरकार द्वारा, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से नियत किया जाएगा। वेतन और वेतनवृद्धि फायदे, अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उससे उद्भूत होंगे।

(5) ज्येष्ठ काल वेतनमान में, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियुक्ति पर ऐसे प्रक्रम पर जो ज्येष्ठ अथवा वेतन में उसके वेतन के बराबर या यदि ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जो उस वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर या (ख) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के न्यूनतम पर, जो भी अधिक हो, नियत किया जाएगा।

(6) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सेवा की किसी सदस्य का वेतन, चयन श्रेणी में नियुक्ति पर, उपरोक्त उप नियम (5) में उसी रीति में नियत किया जाएगा।

(7) चयन श्रेणी में सेवा के किसी सदस्य का वेतन अतिकाल वेतनमान में नियुक्ति पर और उपरोक्त अतिकाल वेतनमान में पहली बार नियुक्ति पर, उपरोक्त उप नियम (2) में दी गई उसी रीति में नियत किया जाएगा।

(8) सेवा के किसी सदस्य के पास सेवा में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रोन्नति पर, उपरोक्त सुसंगत उपनियम में उपबंधित रीति में उसकी प्रोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह निम्नतर वेतनमान में पश्चात्कर्तव्य रूप से वेतन वृद्धि अर्जित करता है, उच्चतर वेतनमान नियत कराने, का विकल्प होगा। पश्चात्कथित मामले में, प्रोन्नति की तारीख को, वेतन पहले सुसंगत उपबंधों के अनुसार उच्चतर वेतनमान नियत किया जाएगा, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी/चयन श्रेणी में प्रोन्नति के मामले में, और उपरोक्त प्रक्रम पर, निम्नतर वेतनमान में नियत किया जाएगा, अन्य मामलों में, निम्नतर वेतनमान अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को उप नियम (2) में यथाउपबंधित रीति में आगे पुनःनियत किया जाएगा। ऐसे किसी मामले में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, उस तारीख से जिसको दूसरे अवसर पर वेतन पुनःनियत किया जाता है, 12 मास की अर्हक सेवा पूरा करने पर आएगी। विकल्प का प्रोन्नति के एक मास के भीतर प्रयुक्त किया जाएगा और वह अंतिम होगा।

**5. वेतनवृद्धि का विनियमन** — (1) नियम 5क या नियम 6 या नियम 7 के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन रहते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती)नियम, 1954 के नियम 7 या नियम 7क के अधीन नियुक्त सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञात वेतनवृद्धि अर्हक सेवा की तारीख वर्ष के अवसान पर प्रोद्भूत होगी।

परंतु इस प्रकार देय होने वाली वेतन वृद्धि उस मास के प्रथम दिन को उद्भूत होगी जिसमें वे उद्भूत हुई होती।

(2) अनुसूची - 1 के खंड 2 और खंड 3 के अधीन रहते हुए, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की दशा में वेतनवृद्धि उस तारीख से जिसको उसका वेतन अनुसूची-1 में अंतर्निष्ठ उपबंधों के अनुसार नियत कर दिया गया है अर्हक सेवा के प्रत्येक वर्ष के पूरा करने पर उद्भूत होंगी और वही सिद्धांत, उन दशाओं में लागू होंगे जहां सेवा में नियुक्ति किसी कांकर पद पर स्थापन के पश्चात् होती है :

परंतु यह कि इस प्रकार देय होने वाली वेतन वृद्धि उस मास के प्रथम दिन को उद्भूत होंगी जिसमें वे उद्भूत हुई होती ।

परंतु यह और कि वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी कांकर पद पर की गई सेवा की विखंडित अवधि को हिसाब में लिया जाएगा ।

(3) सेवा के किसी सदस्य की अगली वेतन वृद्धि जिसका वेतन नियम 3क के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत कर दिया गया है उस तारीख को नियत की जाएगी जिसको वह पुनःवेतनवृद्धि प्राप्त करता जब वह विद्यमान वेतनमान में बने रहता ।

परंतु जहां नियम 3क के उप नियम (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार सेवा के किसी सदस्य का वेतन आगे बढ़ाया जाता है वहाँ अगली वेतन वृद्धि सेवा के किसी सदस्य द्वारा वेतन वृद्धि की तारीख, उस प्रक्रिनिर्देश से जिसके वेतन को इस प्रकार बढ़ाया जाना अनुज्ञात किया गया है, मंजूर की जाएगी :

परंतु यह और कि अन्य दशाओं में, सदस्य के किसी सदस्य की अगली वेतन वृद्धि जिसका वेतन 1 जनवरी, 1996 को नियत किया जाता है, उसी प्रक्रम पर, जिस पर उसे उसी कांकर के उससे कनिष्ठ सेवा के किसी सदस्य के लिए और उससे निम्नतर प्रक्रम पर विद्यमान वेतनमान में वेतन लेने वाले सदस्य के लिए नियत किया जाता है उसी तारीख से मंजूर किया जाएगा जो उसके कनिष्ठ व्यक्ति को अनुज्ञात है, यदि कनिष्ठ व्यक्ति की वेतनवृद्धि की तारीख उससे पूर्वतर है :

परंतु यह भी कि सेवा के किसी सदस्य की दशा में, जो विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी, 1996 को एक वर्ष से अधिक के लिए अधिकतम वेतन ले रहा था, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 1996 को अनुज्ञात की जाएगी ।

(4) चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न अन्यथा ली गई असाधारण छुट्टियों के सिवाय सभी छुट्टी या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के कारण से छुट्टी ली गई है या अध्ययन पर जाने के लिए जो लोकहित में है और जिसके लिए अध्ययन छुट्टी, अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960

के अधीन अन्यथा मंजूर की जाती है सभी छुट्टियों पर जाने के समय उसके द्वारा धारित किसी पद के वेतनमान में लागू वेतन वृद्धि के लिए गणना में ली जाएगी ।

(5) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतनवृद्धि के लिए उक्त अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी कि सेवा का सदस्य उस पद का धारण करना जारी रखता किंतु उसके ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर जाने के लिए न जाता:

परंतु जहाँ इस नियम के अधीन छुट्टी वेतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है वहाँ इसे अंतर्वर्तित अवधि की सीमा तक अगली वेतनवृद्धि तक आस्थगित करने के लिए प्रभावी किया जाएगा ।

(6) नियम 3 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी वेतनमान के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियाँ उसकी सेवा की अवधि जिसमें उस वेतनमान में सेवा की खण्डित तथा पूर्ण सेवा, यदि कोई हो के अनुसार विनियमित होगी तथा इसको भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी । यदि यह -

- (i) किसी पद पर सेवा हो; अथवा
- (ii) उक्त वेतनमान या उससे उच्चतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा हो (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन निगमित या अनिगमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है । )

परन्तु कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सेवा सहित काडर के बाहर पद की सेवा की गणना काडर में वापस जाने पर, वेतनवृद्धि के लिए निम्न शर्तों पर की जाएगी, अर्थात्-

(क) उक्त वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए जिस काडर से वह संबंधित है, उस राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य का अनुमोदन कर दिया गया हो;

(ख) काडर में उसके सभी वरिष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उक्त वेतनमान के वेतन पाने वाले ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें फायदा अनुज्ञात किया जाना है या उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे और कम-से-कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था, या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर-बाह्य पद या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य काडर जिसमें वह हो, की राज्य सरकार के अधीन उक्त वेतनमान के वेतनवाले पद पर था ।

(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति हुई और फायदे उस अवधि तक सीमित होंगे जिसके दौरान वह राज्य सरकार, जिस काडर से वह संबंधित है, के अंतर्गत किसी पद पर वह रहा है ।

(7) सेवा का कोई सदस्य जो केन्द्रीय सरकार के अधीन काडर बाह्य पद धारण कर रहा है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन पद भी है, उस काडर में जिससे वह संबंधित है, राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट काल वेतनमान से ऊपर थे, वेतनमान में किसी पद पर प्रोफार्मा प्रोन्नति अनुवृत्त की जाएगी।

(8) यदि सेवा के किसी सदस्य को अतिकाल वेतनमान या उससे ऊपर के वेतनमान में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई हो, तो प्रोफार्मा प्रोन्नति के अंतर्गत आने वाली अवधि की, उसके संबंधित काडर में वापस जाने तथा उक्त वेतन मान में किसी पद पर नियुक्त होने पर, गणना वेतन के आरंभिक नियतन तथा वेतनवृद्धियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, यथा:-

- (i) संबंधित सेवा के सदस्य से संगत अवधि के दौरान उक्त वेतनमान के लिए नियुक्ति का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया हो;
- (ii) उसके सभी ज्येष्ठ (पद के लिए अनुपयुक्त पाए व्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस वेतनमान में उस तारीख को या उससे पूर्व, जिससे उसे प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई हो, वेतन लेना आरंभ कर दिया हो;
- (iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता, अनुपयुक्तता होने या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी में अपनी इच्छा से प्रोन्नति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही वेतनमान आहरित करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो।
- (iv) ऐसा लाभ 'एक के लिए एक' आधार दिया जाना चाहिए।

(9) जब सेवा का कोई सदस्य काडर-बाह्य पद ऐसे काल वेतनमान में धारण करता हो जो उसके द्वारा पूर्व अवसर पर में धारित किसी काडर बाह्य पद काल वेतनमान के समान हो, तो पश्चात् कथित काडर बाह्य पद पर उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जितना वह आहरित करता था तथा वह, उस अवधि, जिसके दौरान उसने वह अंतिम वेतन तथा उस वेतन के समान वेतनमान स्तर में किसी अन्य अवसर पर वेतन आहरित करता था, की गणना करेगा और इस प्रकार की गई सेवा, उसके उस काडर में वापस आने पर, की गणना तथा उसका आरंभिक वेतन उप नियम (6) में दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत किया जाएगा।

(10) जहाँ सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी से भिन्न उस तारीख को, अवकाश पर है जिस पर उसकी वेतनवृद्धि देय हो, तो उसे उसका लाभ, उस तारीख से, जिससे वह अपना कार्यभार संभालता है, मिलेगा

यदि इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है परन्तु इससे भविष्य में उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी ।

(11) सेवा का कोई भी सदस्य 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतनवृद्धि आहरित करने का वह तक पात्र नहीं होगा जबतक उसने यथाविहित मध्य सेवा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण-V पूरा न कर लिया हो ।

**5 क. वृद्धिरूढ़ वेतनवृद्धि.** कनिष्ठ वेतनमान या ज्येष्ठ वेतनमान या अतिकाल वेतनमान में वेतन आहरित कर सेवा सेवार्त कोई सदस्य, उस वेतनमान में अधिकतम सीमा पर पहुँचने के पश्चात् वेतनवृद्धि की अंतिम दर के समतुल्य सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि के लिए हकदार होगा । ये वेतनवृद्धियाँ अधिकतम तीन बार के अध्येधीन होंगी ।

**6. वेतनवृद्धि रोकना.** राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, जो विभागीय परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर आयोजित परीक्षाओं में असफल हो जाता है, की कोई वेतनवृद्धि उस समय के लिए रोक सकेगी जिन्से समय के लिए वह निदेश दे, लेकिन ऐसी वेतनवृद्धि को रोकें जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा ।

**7. अग्रिम वेतनवृद्धियों का दिया जाना.** भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधी भर्ती किए गए अधिकारी को सेवा की अवधि जिसके पश्चात् वह समय वेतनमान में अपनी हैसियत के अनुरूप दरों पर वेतन आहरित करने का हकदार होगा उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी ज्यों ही वह विभागीय परीक्षा या परीक्षाएँ उत्तीर्ण करता है,

परन्तु इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि यथास्थिति विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या विहित विभागीय परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा पुष्टि हो जाने पर की तारीख से भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी ;

परन्तु यह और सीधे भर्ती किया गया ऐसा व्यक्ति जिसे यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग लेने से इस कारण से छूट प्राप्त है, कि उस सदस्य ने सेवा में आने के पहले ही ऐसी परीक्षा या परीक्षाएँ या इसका भाग उत्तीर्ण कर लिया है, के बारे में यह समझ लिया जाएगा कि इस नियम के लिए उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाएँ या उसका भाग, ऐसी सबसे पहले की परीक्षा, परीक्षाओं या इसके भाग में जिस तारीख से वह उनमें बैठा था उसने उन्हें सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् उत्तीर्ण कर लिया है ।

**8. अनुसूची-II में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य, जब तक वह उस पद को धारण करता है, उक्त**

अनुसूची में पद के लिए उपदर्शित वेतनमान तथा विशेष भत्ते या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जहाँ अनुज्ञेय हो, आहरित करने का हकदार होगा।

परन्तु ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 4 और नियम 5 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा।

**9. अनुसूची-II में सम्मिलित न किए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन**

(1) सेवा का कोई भी सदस्य अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी पद से भिन्न अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि संबंधित राज्य सरकार यथास्थिति अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में, यह घोषणा नहीं कर देती कि उपर्युक्त पद उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।

(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन उतना होगा जितने के लिए वह हकदार होता यदि वह उस पर नियुक्त किया गया होगा जिसे समतुल्य पद घोषित किया गया हो।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न अन्य पद में उस निकाय के पद सम्मिलित हैं निगमित हो अथवा नहीं जो पूर्ण रूप से अथवा सारवान रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हो, का पद शामिल हैं।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों के संबंध में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पर्याप्त कारणों से, जहाँ समीकरण संभव नहीं है, यह घोषणा किए बिना किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकती है कि उपर्युक्त पद अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।

(5) उप नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, जिसके बारे में कोई वेतनमान विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर पर वेतन का आहरण करेगा जो पद से सम्बद्ध कर्तव्यों की प्रकृति और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीन आने वाले पद की दशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

(6) इस उप नियम (6) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त होने पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके सम्बन्ध में कोई वेतन या वेतनमान विहित है, विहित वेतन तथा विहित वेतनमान आहरित करेगा, वेतन की ऐसी दर यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत, वेतनमान में अधिकतम से अधिक नहीं होगी।

इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को, दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह उस समय आहरित करता होगा यदि वह उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त न हुआ होता।

(7) किसी भी समय उप नियम (1) और उप नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न अन्य पदों जिनका वेतन 26,000/- रुपये प्रतिमास है और जिनकी राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर गणना की जाती है, को धारण करने के लिए नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य काडर में वेतन के उस स्तर पर यथास्थिति काडर पदों, संयुक्त संवर्ग से अधिक नहीं हो होगी।

10. एक से अधिक पदों को धारण करने वाले सदस्यों का वेतन - एक समय में एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले सेवा के किसी सदस्य को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी विनियमित की जाएगी ;

(क) संघ के कामकाज से संबंधित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय सिविल सेवा - समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू नियमों ; विनियमों और आदेशों द्वारा

(ख) किसी राज्य के कामकाज से सम्बन्धित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्यों की दशा में जो राज्य सिविल सेवा वर्ग 1 के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमों और आदेशों द्वारा

11. संयुक्त काडर से संबंधित नियम 6, नियम 7 और नियम 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकरण - (1) संयुक्त काडर से सेवा आरंभ करने वाले सेवा के सदस्य की दशा में नियम 6, नियम 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) संयुक्त काडर के सेवा के सदस्यों और पदों के सम्बन्ध में नियम 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

### अनुसूची-I

नियम 4 के उप नियम (3) और नियम (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन के नियतन के सिद्धांत

इस अनुसूची में,

(i) 'वास्तविक वेतन' पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसका यथास्थिति राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा, का सदस्य उस सेवा के काडर में नियुक्ति की अधिष्ठायी हैसियत के कारण या लगातार अस्थायी रूप में या तीन वर्ष तक उच्चतर पद पर स्थानापन्न क्षमता में कार्य करने के कारण परंतु यह जबकि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के लिए लागू वेतनमान में 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् संशोधन न किया हो। यदि वेतनमानों में 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् संशोधन



था/रहा है, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विदेश सेवा के अंतर्गत आने वाले पदों से भिन्न पद है :-

- (क) किसी काडर पद के समय वेतनमान के समान वेतनमान में है ; या
- (ख) किसी काडर पद के स्तर और दायित्वों के समतुल्य,

और संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या चयन सूची में काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्त्वर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत उस काडर पद पर कार्य कर होगा किन्तु काडर से भिन्न खण्ड क के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए या खण्ड ज्येष्ठ काल (ख) पद के संबंध में तीन वर्ष अनधिक के लिए, उसका खण्ड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया उसका प्रारंभिक वेतन उक्त गैर-काडर पद में उसके द्वारा आहरित किए गए/या आहरित किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा ।

परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाणपत्र एक समय में चालू होगा वह भारतीय प्रशासनिक सेवा ( प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम आकार के आधे से अधिक नहीं होगा और इसमें उसी क्रम पालन किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिए गए हैं ।

परंतु यह और कि ऐसा प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब चयन सूची में किसी गैर-काडर पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक ज्येष्ठ अधिकारी, जिसके संबंध में प्रमाणपत्र दिया जाता है, तो चयन सूची में ऐसे प्रत्येक ज्येष्ठ अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी ज्येष्ठ पद पर एक कनिष्ठ चयन सूची का अधिकारी कार्य कर रहा हो ।

परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों के जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है पदों की संख्या उन पदों से अधिक नहीं होगी जिनके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर-काडर पदों पर कार्यरत काडर अधिकारियों की संख्या भा.प्र.से. ( काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची अधीन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति रिजर्व से कम रह जाती है ।

(5) यथास्थिति किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि यथास्थिति किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, के काडर स्थानापन्न के बाद सेवा में नियुक्ति होती है तो ऐसी नियुक्ति के समय वेतन को नियतन करते समय उसको स्थानापन्ने के दौरान नियत किए गए वेतन को ध्यान में रखा जाएगा ।

हुए हैं तो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत मंजूर हुआ है तथा संशोधित वेतनमान में समामेलित कर लिया गया है तो इसे 'वास्तविक वेतन' से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(ii) 'अनुमानित वेतन' पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा जैसा हो, का सदस्य अपनी सेवा के वेतनमान में आहरित करता जिसमें वह स्थायी होता या जिसमें उसने लगातार अस्थायी रूप से या स्थानापन्न क्षमता में तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यरत होता परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा, के लिए लागू वेतनमानों में 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् संशोधन किया हो। यदि 1 जनवरी, 1996 पश्चात् वेतनमान संशोधित किए गए हों तो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई और संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत को पुनरीक्षण वेतनमान में समायोजित कर लिया जाना है या अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(1) नियम 3 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक और उसके नीचे के टिप्पण में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का प्रारम्भिक वेतन उसके वास्तविक वेतन के ठीक ऊपर के ज्येष्ठ वेतनमान के स्तर पर नियत किया जाएगा।

लेकिन यह भी शर्त होगी कि यदि इस वेतनमान के विभिन्न संघटकों के लिए सामान्य हो तो वेतन ज्येष्ठ वेतनमान के निम्नतर या निम्नतर संघटकों, पर नियत किया जाएगा।

(2) किसी प्रोन्नत अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा पर चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, की सेवा में उसके वास्तविक वेतन में या कल्पित वेतन में वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि या वेतन वृद्धि के लिए हकदार होने या परीक्षा को अवधि के दौरान जबतक कि परीक्षा की अवधि भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के बढाई न जाए, राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के उच्चतर वेतनमान में स्थायीकरण हो, की स्थिति में वह राज्य सिविल सेवा या गैर राज्य सिविल सेवा जैसा भी मामला हो, में बढे हुए अपने वेतन के आधार पर इस अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार अपने वेतन की पुनर्संगणना उस तरीके से करवाने का हकदार होगा जैसा कि वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हुआ था।

(3) यदि कोई यथास्थिति प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, राज्य सिविल सेवा या गैर राज्य सिविल सेवा, यथास्थिति हो, में परीक्षा अवधि के दौरान, जब तक कि उसकी परीक्षा को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियम के नियम 3 के उप नियम (3) के अर्थातर्गत में विस्तारित न की जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार से वहाँ पर उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन में की गई वृद्धि की पुनर्गणना ऐसी वृद्धि की प्रभावी तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्धित उसके वेतन के आधार पर इस अनुसूची में विहित सिद्धान्तों के अनुसार की जाएगी।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें यथास्थिति कोई प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख को किसी ऐसे पद पर लगातार पदधारण कर रहा

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन कभी भी उसके उस मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसे उस तारीख को सीधी भर्ती के रूप में मिल रहा था जिसको वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर नियुक्त किया गया था।

राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति या भारतीय प्रशासनिक सेवा के काडर पद पर स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने पर उनके वेतन का नियतन प्रपत्र 'क' और 'ख' में किया जाएगा।

#### प्रपत्र-क

भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर पदों पर स्थानापन्न कार्य करने के लिए नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन के नियतन की बाबत प्रपत्र।

1. अधिकारी का नाम:
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/किसी काडर पद पर स्थानापन्न कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का पदनाम:
4. भा.प्र.से. में नियुक्ति या किसी काडर पद में स्थानापन्न कार्य करने हेतु नियुक्ति की तारीख का राज्य सिविल सेवा में वेतनमान और आहरित वेतन।
5. क्या अधिकारी क्रम संख्या 3 में ऊपर उल्लिखित पद पर अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्यरत था
6. यदि तीन वर्षों से कम अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा था तो अधिष्ठायी पद क्या था ?
7. अधिष्ठायी पद या उस पद जिस पर वह तीन वर्षों या अधिक के लिए निरंतर और विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, का वेतन और वेतनमान।
8. इस सेवामें नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के व्योरे, इन पदों पर आहरित वेतन और वेतनमान।
9. क्या क्रम संख्या 4 और 7 पर निर्दिष्ट वेतनमान 1.1.1996 को लागू थे।
10. यदि ऐसा है तो, निम्नलिखित के संदर्भ में अनुज्ञेय महंगाई भत्ता कितना था

(क) अधिष्ठायी पद

(ख) स्थानापन्न पद

( 1.1.1996 को लागू महंगाई भत्ते की दर से न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने की तारीख को लागू महंगाई की दर से )

11. यदि क्रम संख्या 9 का उत्तर नहीं में है तो 1.1.96 के पश्चात् पहली बार वेतनमान संशोधित कब किया गया था और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद का संशोधन पूर्व वेतनमान क्या था ।
12. 1.1.96 के पश्चात् अनुज्ञेय महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन/अंतरिम राहत की मात्रा और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद के वेतनमान में इसे आमेलित करने की मात्रा कितनी थी ?
13. राज्य सिविल सेवा के श्रेणी-1 या समूह 'क' की सेवा में पूरे किए गए वर्षों की संख्या
14. वेतन नियत करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार

### प्रपत्र 'ख'

भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए गैर-राज्य सिविल सेवा सेवा अधिकारियों के वेतन के नियतन हेतु प्रपत्र-

1. अधिकारी का नाम
2. सेवा में नियुक्ति की तारीख
3. सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का पदनाम
4. क्रम संख्या 3 निर्दिष्ट पद का वेतन और वेतनमान
5. क्या वेतन अधिष्ठायी या स्थानापन्न आधार पर था
6. यदि 3 वर्ष से कम अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में कार्य किया है तो मूल वेतन क्या था ?
7. उस पद का पदनाम और वेतनमान क्या था जिस पर अधिकारी अधिष्ठायी से कार्यरत था
8. इस सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों का विस्तृत ब्यौरा इन पदों के वेतनमान और आहरित वेतन ।
9. उल्लेख करें कि क्या अधिकारी अधिष्ठायी पद और वह पद और जिन पर अधिकारी तीन वर्षों या अधिक के लिए वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा था, के वेतनमान 1.1.96 को लागू थे
10. यदि उपर्युक्त क्र.सं. 9 के लिए उत्तर 'हाँ' है तो 1.1.96 को अधिकारी को अनुज्ञेय लागू दर से महंगाई भत्ता क्या था

(क) अधिष्ठायी पद

(ख) स्थानापन्न पद

11. यदि उपर्युक्त क्र.सं. 9 के लिए दिया गया उत्तर 'नहीं' है तो उन पदों का संशोधन-पूर्व वेतनमान क्या था जिन पर अधिकारी कार्यरत था:-

- (क) अधिष्ठायी पद  
(ख) स्थानापन्न पद

12. पुनरीक्षित वेतनमान में समाकलित महंगाई भत्ते की क्या मात्रा थी -

- (क) अधिष्ठायी पद  
(ख) स्थानापन्न पद

13. पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर पूरे किए वर्षों की संख्या

14. वेतन का नियतन करने के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार

क- राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद  
अनुसूची-II

क.	आन्ध्र प्रदेश	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	महानिदेशक डॉ. मारी चैन्ना रेड्डी, मानव संसंधान विकास संस्थान, आन्ध्र प्रदेश	26,000/- रु. (नियत)
3.	मुख्य आयुक्त, भूमि प्रशासन	26,000/- रु. (नियत)
4.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	मुख्य चुनाव अधिकारी और सरकारी के पदेन प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
6.	आयुक्त, याणिज्य-कर	22400-525-24500/-रु.
7.	आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	शर्करा आयुक्त और निदेशक	18400-500-22400/-रु.
9.	पंचायती राज आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
10.	हथकरधा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
11.	उद्योग आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
12.	ग्रामीण विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	रोजगार और प्रशिक्षण आयुक्त	18400-500-22400/-रु.

14.	महिला विकास और बाल कल्याण आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
15.	जनजाति कल्याण आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
16.	रेशम उत्पादन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
17.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
18.	वृत्तिदान आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
19.	सहकारिता आयुक्त और सहकारी समिति रजिस्ट्रार	18400-500-22400/-रु.	
20.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
21.	विभागीय जाँच आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
22.	आयुक्त-सह-निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	18400-500-22400/-रु.	
23.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
24.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
25.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
26.	राहत आयुक्त और सरकार के पदेन सचिव	18400-500-22400/-रु.	
27.	स्थानिक आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश भवन, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.	
	अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र		
	अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
3.	आयुक्त-सह-सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./आर.डब्ल्यू.डी.)	18400-500-22400/-रु.	
4.	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	18400-500-22400/-रु.	
5.	मंडल आयुक्त (पूर्व)	18400-500-22400/-रु.	
6.	मंडल आयुक्त (पश्चिम)	18400-500-22400/-रु.	
7.	आयुक्त-सह-सचिव (गृह)	18400-500-22400/-रु.	
8.	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	18400-500-22400/-रु.	
	गोवा सरकार के अधीन पद		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.	
3.	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	18400-500-22400/-रु.	
4.	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और स्वास्थ्य)	18400-500-22400/-रु.	
	मिजोरम सरकार के अधीन पद		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	आयुक्त/सचिव (विकास)	18400-500-22400/-रु.	

3.	आयुक्त/सचिव (वित्त)	18400-500-22400/-रु.
4.	आयुक्त/सचिव (राजस्व)	18400-500-22400/-रु.
5.	आयुक्त/सचिव (गृह)	18400-500-22400/-रु.
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के अधीन पद	
1.	मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
2.	आयुक्त-सह-सचिव (विकास)	18400-500-22400/-रु.
3.	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	18400-500-22400/-रु.
4.	आयुक्त-सह-सचिव (पोत परिवहन और परिवहन)	18400-500-22400/-रु.
	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के अधीन पद	
1.	प्रशासक चण्डीगढ़ के सलाहकार	22400-525-24500/-रु.
2.	सचिव (गृह)	18400-500-22400/-रु.
3.	सचिव (वित्त)	18400-500-22400/-रु.
	संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव/दादर तथा नगर हवेली के अधीन पद	
1.	विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
2.	वित्त सचिव	18400-500-22400/-रु.
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन पद	
1.	मुख्य सचिव	28,000/- रु. (नियत)
2.	प्रधान सचिव (गृह)	22400-525-24500/-रु.
3.	प्रधान सचिव (वित्त)	22400-525-24500/-रु.
4.	प्रधान सचिव (यू.डी.)	22400-525-24500/-रु.
5.	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	22400-525-24500/-रु.
6.	आयुक्त और सचिव (विकास)	18400-500-22400/-रु.
7.	आयुक्त और सचिव (पी.डब्ल्यू.डी./एल. और बी/एल.एस.जी.)	18400-500-22400/-रु.
8.	आयुक्त और सचिव (उद्योग)	18400-500-22400/-रु.
9.	आयुक्त/सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	18400-500-22400/-रु.
10.	आयुक्त/सचिव (योजना और अवसंरचना)	18400-500-22400/-रु.
11.	सचिव (पर्यटन, सांस्कृतिक, परास्तत्य और अकादमी)	18400-500-22400/-रु.
12.	सचिव (जल और विद्युत)	18400-500-22400/-रु.
13.	सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा)	18400-500-22400/-रु.

14.	आयुक्त (बिक्री कर)	18400-500-22400/-रु.
15.	निदेशक, सतर्कता	18400-500-22400/-रु.
16.	सदस्य, अपील अधिकरण विक्रय कर	18400-500-22400/-रु.
17.	शिक्षा निदेशक	18400-500-22400/-रु.
18.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
19.	आयुक्त (अपील)	18400-500-22400/-रु.
20.	उप-राज्यपाल का सचिव	18400-500-22400/-रु.
21.	आयुक्त और सचिव (शिक्षा)	18400-500-22400/-रु.
22.	आयुक्त और सचिव (परिवहन)	18400-500-22400/-रु.
	पांडिचेरी सरकार के अधीन पद	
1.	मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
2.	सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
3.	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण)	18400-500-22400/-रु.
	असम-मेघालय	
	असम	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अध्यक्ष, असम प्रशासनिक अधिकरण	26,000/- रु. (नियत)
3.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	अपर मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
6.	कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास आयुक्त तथा सरकार के विशेष सचिव	18400-500-22400/-रु.
7.	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
8.	सरकार के आयुक्त और सचिव	18400-500-22400/-रु.
9.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
10.	सरकार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी और पदेन आयुक्त तथा सचिव	18400-500-22400/-रु.
	मेघालय	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विकास आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
3.	आयुक्त मंडल	18400-500-22400/-रु.
4.	आयुक्त और सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.



	बिहार	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)
3.	विकास आयुक्त	26,000/- रु. (नियत)
4.	कृषि उत्पादन आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
5.	आयुक्त और सचिव (वित्त)	22400-525-24500/-रु.
6.	आयुक्त और सचिव (गृह)	22400-525-24500/-रु.
7.	सतर्कता आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
8.	आयुक्त और सचिव, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, राजस्व और राजस्व और भूमि सुधार और उद्योग	22400-525-24500/-रु.
9.	आयुक्त और सचिव, कार्मिक विभाग	22400-525-24500/-रु.
10.	आयुक्त और सचिव, स्वास्थ्य विभाग	22400-525-24500/-रु.
11.	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग	22400-525-24500/-रु.
12.	राहत और पुनर्वास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
14.	आयुक्त, वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.
15.	अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	18400-500-22400/-रु.
16.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
17.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी-सह-सचिव	18400-500-22400/-रु.
18.	सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग	18400-500-22400/-रु.
19.	सचिव, कल्याण	18400-500-22400/-रु.
20.	सचिव, शहरी विकास	18400-500-22400/-रु.
21.	सचिव, खाद्य, नागरिक पूर्ति और वाणिज्य	18400-500-22400/-रु.
22.	सचिव, ऊर्जा विभाग	18400-500-22400/-रु.
23.	सचिव, मंत्रिमंडल सचिव.	18400-500-22400/-रु.
24.	सचिव, वन और पर्यावरण	18400-500-22400/-रु.
25.	सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	18400-500-22400/-रु.
26.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
27.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	18400-500-22400/-रु.
28.	सचिव, पशुपालन और मछली पालन विभाग	18400-500-22400/-रु.
29.	सचिव, सहकारी विभाग	18400-500-22400/-रु.
30.	सचिव, भवन निर्माण विभाग	18400-500-22400/-रु.
31.	सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	18400-500-22400/-रु.
32.	सचिव, लघु सिंचाई विभाग	18400-500-22400/-रु.

33.	सचिव, सूचना और जन सम्पर्क विभाग	18400-500-22400/-रु.	
34.	सचिव, परिवहन विभाग	18400-500-22400/-रु.	
35.	सचिव, संस्थागत वित्त और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	18400-500-22400/-रु.	
36.	सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण इंजीनियरी विभाग	18400-500-22400/-रु.	
37.	महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण-सह-सचिव	18400-500-22400/-रु.	
38.	विभागीय जांच आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
39.	लोकायुक्त सचिव	18400-500-22400/-रु.	
40.	सचिव, उत्पादन शुल्क और मद्यनिषेध विभाग	18400-500-22400/-रु.	
	छत्तीसगढ़		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)	
3.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.	
4.	कृषि उत्पादन आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
5.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	18400-500-22400/-रु.	
6.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
7.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.	
8.	आयुक्त, वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.	
9.	आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.	
10.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.	
11.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
12.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
13.	निदेशक, प्रशासन अकादमी	18400-500-22400/-रु.	
14.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
15.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
16.	आयुक्त, जनजाति विकास	18400-500-22400/-रु.	
17.	आयुक्त, उद्योग	18400-500-22400/-रु.	
18.	आयुक्त, खजाना, अल्प बचत और लॉटरी	18400-500-22400/-रु.	
	गुजरात		
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	सरकार के अपर मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
3.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.	
4.	प्रशिक्षण आयुक्त और निदेशक, सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान	22400-525-24500/-रु.	

5.	राज्यपाल के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
6.	विक्रय आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
7.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
8.	विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
9.	उद्योग आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
10.	विभागीय जॉच आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
11.	व्यवस्थापन आयुक्त और भूमि रिकार्ड निदेशक	18400-500-22400/-रु.
12.	भूमि सुधार आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	कुटीर और ग्रामोद्योग आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
14.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
15.	उच्च शिक्षा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
16.	सदस्य, शहरी भूमि अधिकरण	18400-500-22400/-रु.
17.	मछली पालन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
18.	स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
19.	महिला और बाल विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
20.	भू-विज्ञान और खनन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
21.	ग्रामीण विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
22.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	18400-500-22400/-रु.
हरियाणा		
1.	सरकार के मुख्य सचिव	28,000/- रु. (नियत)
2.	वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव	28,000/- रु. (नियत)
3.	वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव/सदस्य, विक्रय कर अधिकरण	22400-525-24500/-रु.
4.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
5.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
6.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
7.	मद्यनिषेध, उत्पादन शुल्क और कराधान आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
9.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
10.	निदेशक, कृषि	18400-500-22400/-रु.
11.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	18400-500-22400/-रु.
12.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
13.	निदेशक, उद्योग	18400-500-22400/-रु.
14.	निदेशक, नगर और ग्रामीण योजना-सह-शहरी सम्पदा और कालोनी	18400-500-22400/-रु.
15.	निदेशक, उच्च शिक्षा	18400-500-22400/-रु.

16.	राज्य परिवहन नियंत्रक	18400-500-22400/-रु.
	हिमाचल प्रदेश	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	वित्तीय आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
3.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
4.	आयुक्त-सह-सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
5.	आयुक्त-सह-सचिव (लोक आयुक्त)	18400-500-22400/-रु.
6.	मुख्य चुनाव अधिकारी-सह-सचिव (चुनाव)	18400-500-22400/-रु.
7.	निदेशक, उद्योग	18400-500-22400/-रु.
8.	उत्पादन शुल्क और कराधान आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
9.	निदेशक, सामाजिक और महिला कल्याण	18400-500-22400/-रु.
10.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
	जम्मू और कश्मीर	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
3.	वित्तीय आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
4.	अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण	22400-525-24500/-रु.
5.	आयुक्त और सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
6.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
7.	स्थानिक आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
	झारखण्ड	
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	विकास आयुक्त	26,000/- रु. (नियत)
3.	आयुक्त और सचिव/प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
5.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
6.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	18400-500-22400/-रु.
7.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
	कर्नाटक	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	सरकार के प्रधान मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)

3.	सरकार के प्रधान मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त	28,000/- रु. (नियत)
4.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	अध्यक्ष, कर्नाटक अपील अधिकरण	22400-525-24500/-रु.
6.	सरकार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी और पदेन प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
7.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
8.	स्थानिक आयुक्त, कर्नाटक भवन	22400-525-24500/-रु.
9.	महानिदेशक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	22400-525-24500/-रु.
10.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
11.	वाणिज्य-कर आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
12.	महानरीक्षक, पंजीयन और स्टाम्प आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
14.	उद्योग और वाणिज्य निदेशक और औद्योगिक विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
15.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
16.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति और निदेशक लेखापरीक्षक	18400-500-22400/-रु.
17.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
18.	परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
19.	आयुक्त, गन्ना विकास और निदेशक, चीनी	18400-500-22400/-रु.
20.	आयुक्त, सार्वजनिक अनुदेश	18400-500-22400/-रु.
21.	आयुक्त, रेशम-उत्पादन विकास और आयुक्त, रेशम उत्पादन	18400-500-22400/-रु.
22.	महाविद्यालय शिक्षा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
23.	कृषि आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
25.	वाटरशेड (जलसंभर) विकास विभाग आयुक्त और कृषि तथा वागबानी विभाग सरकार के ई/ओ सचिव	18400-500-22400/-रु.
26.	सचिव, मालनाड क्षेत्र विकास बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
27.	कार्यपालक निदेशक, कर्नाटक जलसंवर्धन संघ	18400-500-22400/-रु.
28.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
29.	पिछड़ा वर्ग आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
30.	सार्वजनिक अनुदेश आयुक्त, हुबली	18400-500-22400/-रु.
31.	सार्वजनिक अनुदेश आयुक्त, गुलबर्गा	18400-500-22400/-रु.
32.	समाज कल्याण आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
33.	पर्यटन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
34.	रोजगार और प्रशिक्षण आयुक्त	18400-500-22400/-रु.

35.	सूचना आयुक्त और ई/ओ सचिव, आई.टी.वाई.एस.	18400-500-22400/-रु.
36.	सदस्य, कर्नाटक अपील अधिकरण	18400-500-22400/-रु.
37.	आयुक्त, सर्वेक्षण, व्यवस्थापन और भूमि अभिलेख	18400-500-22400/-रु.
	केरल	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
3.	सरकार के मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	कृषि उत्पादन आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
5.	आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
6.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
7.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
8.	निदेशक, कृषि	18400-500-22400/-रु.
9.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
10.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
11.	उद्योग और वाणिज्य निदेशक	18400-500-22400/-रु.
12.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
	मध्य प्रदेश	
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)
3.	अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी	26,000/- रु. (नियत)
4.	प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	कृषि उत्पाद आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
6.	विकास आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
7.	प्रशासनिक सदस्य, राजस्व बोर्ड	22400-525-24500/-रु.
8.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
9.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
10.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
11.	आयुक्त, वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.
12.	भूमि रिकार्ड और व्यवस्थापन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	आयुक्त, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
14.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
15.	राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश	18400-500-22400/-रु.
16.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
17.	निदेशक, प्रशासन अकादमी	18400-500-22400/-रु.

18.	आयुक्त, उद्योग	18400-500-22400/-रु.
19.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
20.	सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश	18400-500-22400/-रु.
21.	महानिरीक्षक, पंजीयन और अधीक्षक, स्टाम्प	18400-500-22400/-रु.
22.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
23.	आयुक्त, जनजाति विकास	18400-500-22400/-रु.
24.	आयुक्त, जनजाति विकास	18400-500-22400/-रु.
25.	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	18400-500-22400/-रु.
26.	आयुक्त, महिला और बाल विकास	18400-500-22400/-रु.
27.	आयुक्त, सार्वजनिक अनुदेश	18400-500-22400/-रु.
28.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	18400-500-22400/-रु.
29.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	18400-500-22400/-रु.
30.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा	18400-500-22400/-रु.
	महाराष्ट्र	
1.	सरकार के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
3.	अपर सरकार के मुख्य सचिव, विदर्भ विकास	26,000/- रु.
4.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	विभागीय जाँच आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
6.	महानिदेशक, विकास और प्रशासन, यशवन्त राव चव्हाण अकादमी	22400-525-24500/-रु.
7.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
8.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
9.	बिक्री कर आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
10.	व्यवस्थापन आयुक्त और निदेशक, भूमि रिकार्ड	18400-500-22400/-रु.
11.	सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
12.	सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार	18400-500-22400/-रु.
13.	खाद्य और औषध प्रशासन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
14.	मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी और सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
15.	आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना	18400-500-22400/-रु.
16.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी और सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
17.	विकास आयुक्त उद्योग	18400-500-22400/-रु.
18.	मद्यनिषेध और उत्पाद-शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
19.	आयुक्त, शर्करा	18400-500-22400/-रु.

20.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
21.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
22.	विशेष आयुक्त, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
23.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
24.	डेरी विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
25.	कृषि आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
26.	जनजाति विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
	मणिपुर-त्रिपुरा	
	मणिपुर	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत) (30 वर्ष की सेवा के पश्चात्)
2.	अपर मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
3.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
5.	महानिदेशक, राज्य प्रशिक्षण अकादमी	18400-500-22400/-रु.
6.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
7.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
8.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
	त्रिपुरा	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत) (30 वर्ष की सेवा के पश्चात्)
2.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
3.	सरकार के आयुक्त-सह-सचिव	18400-500-22400/-रु.
4.	स्थानिक आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
5.	राज्यपाल के विशेष सचिव	18400-500-22400/-रु.
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद्	18400-500-22400/-रु.
	नागालैण्ड	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के लिए गृह आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
3.	अपर मुख्य सचिव के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के लिए अपर मुख्य सचिव, योजना और समन्वय	22400-525-24500/-रु.
4.	प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.



5.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
6.	आयुक्त और सचिव के रूप में पुनःपदनामित किए जाने के लिए सरकार के आयुक्त और सचिव	18400-500-22400/-रु.
7.	आयुक्त के रूप में पुनःपदनामित किए जाने के लिए, मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	18400-500-22400/-रु.
9.	राज्यपाल के विशेष सचिव के रूप में पुनःपदनामित किए जाने के लिए, राज्यपाल के विशेष सचिव	18400-500-22400/-रु.
10.	आयुक्त, कर और उत्पादन शुल्क	18400-500-22400/-रु.
11.	स्थानिक आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
उड़ीसा		
1.	सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त	26,000/- रु. (नियत)
2.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)
3.	मुख्य प्रशासक (विशेष क्षेत्र विकास) और पदेन सदस्य, राजस्व बोर्ड और सरकार के विशेष मुख्य सचिव)	26000/- रु. (नियत)
4.	सरकार के अपर मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	विशेष राहत आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
6.	कृषि उत्पाद आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
7.	सरकार प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
8.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	22400-525-24500/-रु.
9.	सरकार के अपर विकास आयुक्त और सचिव, योजना और समन्वय	18400-500-22400/-रु.
10.	आयुक्त, जनजाति और हरिजन कल्याण	22400-525-24500/-रु.
11.	महानिदेशक, प्रशिक्षण समन्वय, गोपाबन्धु प्रशासन अकादमी, भुवनेश्वर	22400-525-24500/-रु.
12.	राजस्व मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
13.	आयुक्त भूमि और सुधार	18400-500-22400/-रु.
14.	आयुक्त वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.
15.	आयुक्त भूमि सुधार और व्यवस्थापन	18400-500-22400/-रु.
16.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
17.	आयुक्त चकबंदी	18400-500-22400/-रु.
18.	आयुक्त-सह-राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
19.	आयुक्त-सह-मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
20.	आयुक्त-सह-सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.

21.	सरकार के विशेष सचिव	18400-500-22400/-रु.
	पंजाब	
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	वित्त आयुक्त (विकास)	26,000/- रु. (नियत)
3.	वित्त आयुक्त/सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	वित्त आयुक्त (अपील)	22400-525-24500/-रु.
5.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी और सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
6.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
7.	उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
9.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	18400-500-22400/-रु.
10.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
11.	निदेशक/कार्यपालक निदेशक, पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान	18400-500-22400/-रु.
12.	रजिस्ट्रार सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
13.	निदेशक खाद्य और नागरिक आपूर्ति	18400-500-22400/-रु.
14.	निदेशक संस्थागत वित्त और बैंकिंग और सरकार के सार्वजनिक उद्यम व्यूरो-सह-सचिव	18400-500-22400/-रु.
15.	स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
	राजस्थान	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)
3.	अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण	26,000/- रु. (नियत)
4.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
5.	अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड	22400-525-24500/-रु.
6.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
7.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	विभागीय जाँच आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
9.	आयुक्त, वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.
10.	आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास	18400-500-22400/-रु.
11.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
12.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.

13.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
14.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
15.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
16.	उत्पादन शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
17.	आयुक्त, श्रम और रोजगार	18400-500-22400/-रु.
18.	आयुक्त, उद्योग	18400-500-22400/-रु.
19.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
20.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी और सरकार के पदेन प्रधान सचिव, चुनाव	18400-500-22400/-रु.
	सिक्किम	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	अपर मुख्य सचिव	22400-525-24500/-रु.
3.	प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
4.	आयुक्त-सह-सचिव	18400-500-22400/-रु.
	तमिलनाडु	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	सतर्कता आयुक्त	26,000/- रु. (नियत)
3.	प्रधान आयुक्त, राजस्व प्रशासन	26,000/- रु. (नियत)
4.	विशेष आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
5.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी और सरकार के सचिव	22400-525-24500/-रु.
6.	मद्यनिषेध, उत्पाद-शुल्क और मादक द्रव्य आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
7.	कृषि आयकर आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
8.	सचिव, राज्य योजना आयोग	22400-525-24500/-रु.
9.	परिवहन आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
10.	आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही, मद्रास	18400-500-22400/-रु.
11.	स्थानिक आयुक्त, तमिलनाडु हाऊस, नई दिल्ली	18400-500-22400/-रु.
12.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
13.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
14.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
15.	उद्योग आयुक्त और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	18400-500-22400/-रु.
16.	निदेशक, शर्करा	18400-500-22400/-रु.
17.	नागरिक आपूर्ति आयुक्त	18400-500-22400/-रु.

18.	निदेशक, नगर पंचायत	18400-500-22400/-रु.	
19.	आयुक्त, दुग्ध उत्पाद	18400-500-22400/-रु.	
20.	रजिस्ट्रार सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.	
21.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
22.	आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन	18400-500-22400/-रु.	
23.	आयुक्त, ग्राम विकास	18400-500-22400/-रु.	
	उत्तरांचल		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	महानिदेशक उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल	26,000/- रु. (नियत)	
3.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.	
4.	मुख्य राजस्व आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
5.	प्रधान सचिव और वन और ग्रामीण विकास आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
6.	प्रधान सचिव और अवसंरचना विकास आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
7.	प्रधान सचिव और समाज कल्याण आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	
8.	स्थानिक आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
9.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
10.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
11.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.	
12.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.	
13.	आयुक्त उत्पाद-शुल्क	18400-500-22400/-रु.	
14.	आयुक्त कर	18400-500-22400/-रु.	
15.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पर्यटन बोर्ड	18400-500-22400/-रु.	
	उत्तर प्रदेश		
1.	मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)	
2.	अध्यक्ष राजस्व बोर्ड और सलाहकार भूमि सुधार	26,000/- रु. (नियत)	
3.	अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	26,000/- रु. (नियत)	
4.	अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	26,000/- रु. (नियत)	
5.	महानिदेशक, प्रशिक्षण	26,000/- रु. (नियत)	
6.	मुख्य आयुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर)	22400-525-24500/-रु.	
7.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.	
8.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	22400-525-24500/-रु.	
9.	मुख्य उत्पाद आयुक्त	22400-525-24500/-रु.	

10.	औद्योगिक विकास आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
11.	समाज कल्याण आयुक्त	22400-525-24500/-रु.
12.	राज्यपाल के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
13.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
14.	महानिदेशक, राज्य ग्राम विकास संस्थान	22400-525-24500/-रु.
15.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
16.	सरकार के सचिव	18400-500-22400/-रु.
17.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
18.	बिक्री कर आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
19.	ग्राम विकास आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
20.	परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
21.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	18400-500-22400/-रु.
22.	निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	18400-500-22400/-रु.
23.	निदेशक, उद्योग	18400-500-22400/-रु.
24.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
25.	निदेशक हथकरघा	18400-500-22400/-रु.
26.	गन्ना आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
27.	सचिव, राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
28.	महानिदेशक, कारागार	18400-500-22400/-रु.
29.	महानिदेशक, पर्यटन	18400-500-22400/-रु.
30.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
31.	अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-॥	18400-500-22400/-रु.
32.	सदस्य (न्यायिक) राजस्व बोर्ड	18400-500-22400/-रु.
33.	आयुक्त, खाद्य	18400-500-22400/-रु.
34.	मनोरंजन कर आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
35.	महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार और स्टाम्प	18400-500-22400/-रु.
36.	चकबंदी आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
37.	मुख्य सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी	18400-500-22400/-रु.
38.	निदेशक, संस्कृति	18400-500-22400/-रु.
	पश्चिम बंगाल	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	26,000/- रु. (नियत)
2.	महा आयुक्त, भूमि सुधार	26000/- रु. (नियत)
3.	आयुक्त, खाद्य और पदेन सचिव, खाद्य और आपूर्ति विभाग	26000/- रु. (नियत)

4.	प्रधान सचिव, वन	26000/- (नियत) रु.
5.	सरकार के प्रधान सचिव (गृह, वित्त, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, राहत, पशु संसाधन विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग)	22400-525-24500/-रु.
6.	सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/-रु.
7.	मंडल आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
8.	सचिव/सरकार के विशेष सचिव	18400-500-22400/-रु.
9.	भूमि सुधार आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
10.	निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	18400-500-22400/-रु.
11.	राज्यपाल के सचिव	18400-500-22400/-रु.
12.	मुख्यमंत्री के सचिव	18400-500-22400/-रु.
13.	निदेशक समाज कल्याण	18400-500-22400/-रु.
14.	आयुक्त, वाणिज्य-कर	18400-500-22400/-रु.
15.	श्रम आयुक्त	18400-500-22400/-रु.
16.	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	18400-500-22400/-रु.
17.	आयुक्त, पंचायत	18400-500-22400/-रु.
18.	आयुक्त, परिवार कल्याण	18400-500-22400/-रु.
19.	आयुक्त, विद्यालय शिक्षा	18400-500-22400/-रु.
20.	आयुक्त, उत्पादन शुल्क	18400-500-22400/-रु.

ख - वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते के पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के पद । (1) राज्य काडर की चयन श्रेणी में पदों की संख्या, राज्य में ज्येष्ठ पदों के न्यूनतम 15% के अधीन रहते हुए राज्य में ज्येष्ठ वेतनमान में पदों की संख्या में कमी करके राज्य में ज्येष्ठ पदों की कुल संख्या में 20% के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण I - “राज्य में ज्येष्ठ पद” अभिव्यक्ति से भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची की मद 1 में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन ज्येष्ठ पदों से अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण II - चयन श्रेणी पदों की संख्या प्राधिकृत संख्या के आधार पर, इस खण्ड के अधीन निकाली जाएगी और किसी काडर में अस्थायी परिवर्धन/किसी काडर पद के प्रास्थगन में अस्थायी तौर पर बने रहने के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किसी भी पद के लिए वैयक्तिक रूप में अथवा ऐसे पदों के समूह अथवा श्रेणी के काडर में विशेष भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे।

(3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो खण्ड (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए, कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 400/- रु., ज्येष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 600/- रु., कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए 800/- रु. और चयन श्रेणी के पदों के लिए 1000/- रु. होगी।

(4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के पद अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किन्तु ऐसे पदों से संबंधित किसी भी विशेष भत्ते की स्वीकृति के लिए यह संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर होगा।

क्र.सं.	आन्ध्र प्रदेश	
1.	सरकार के अपर/संयुक्त/उप-सचिव	
2.	मुख्य आयुक्त के सचिव, भूमि प्रशासन	
3.	मुख्य आयुक्त के अपर/संयुक्त सचिव, भूमि प्रशासन	
4.	कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	
5.	विशेष कलेक्टर	
6.	विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि परिसीमन	
7.	मुख्य आयुक्त भूमि प्रशासन के सचिव	
8.	संयुक्त कलेक्टर	
9.	संयुक्त आयुक्त, उत्पाद-शुल्क (प्रवर्तन)	
10.	उपायुक्त (उत्पाद-शुल्क)	
11.	आयुक्त के सचिव (उत्पाद-शुल्क)	
12.	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	
13.	निदेशक, पर्यटन	
14.	सचिव, आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग	

<sup>40</sup> तारीख 21.12.98 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या-14021/4/98-अ.भा.से.(II)-क द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>41</sup> तारीख 26.07.74 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या-10/19/74-अ.भा.से.(II)-ख द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>42</sup> तारीख 15.09.64 के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-1/22/63-अ.भा.से.(II)-ख द्वारा तारीख 01.03.1962 से सम्मिलित/पुनः सांख्यांकित।

15.	परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्	
-----	---	--

16.	निदेशक, व्यवस्थापन, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख	
17.	निदेशक, समाज कल्याण	
18.	संयुक्त आयोग (वाणिज्य-कर)	
19.	उपायुक्त ((वाणिज्य-कर))	
20.	आयुक्त के सचिव (वाणिज्य-कर)	
21.	मुख्य राशन अधिकारी	
22.	निदेशक, आसवनी और उत्पाद-शुल्क आयुक्त के अपर सचिव	
	अरुणाचल प्रदेश - गोवा - मिजोरम - संघ राज्य क्षेत्र	
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	सचिव (उद्योग)	
2.	सचिव (आपत्ति और परिवहन)	
3.	सचिव (सामान्य प्रशासन))	
4.	संयुक्त सचिव (राजनीतिक)	
5.	संयुक्त सचिव (योजना और विकास)	
6.	मुख्यमंत्री के सचिव	
7.	राज्यपाल के सचिव	
8.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
9.	निदेशक, आपत्ति और परिवहन	
10.	सचिव, नागरिक आपत्ति	
11.	उपायुक्त (जिला)	
	गोवा	
1.	राज्यपाल के सचिव	
2.	मुख्यमंत्री के सचिव	
3.	सरकार के सचिव	
4.	आयुक्त (विक्रय कर)	
5.	निदेशक, उद्योग और खान	
6.	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	
7.	आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	
	मिजोरम	
1.	राज्यपाल के सचिव	
2.	मुख्यमंत्री के सचिव	
3.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	



4.	निदेशक, आपति और परिवहन	
5.	निदेशक, उद्योग	
6.	उपायुक्त (जिला)	
7.	सचिव	
8.	संयुक्त सचिव (वित्त)	
9.	संयुक्त सचिव (राजनीतिक और सतर्कता)	
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
1.	उप-राज्यपाल के सचिव	
2.	उपायुक्त (जिला)	
3.	उप विकास आयुक्त/विशेष सचिव	
	चण्डीगढ़	
1.	उपायुक्त (जिला)	
2.	संयुक्त सचिव (वित्त)	
	दमन और दीव/दादर तथा नगर हवेली	
1.	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (दमन, दीव/दादर तथा नगर हवेली)	
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
1.	उपायुक्त (जिला)	
2.	सचिव (सेवाएं)	
3.	निदेशक, प्रशिक्षण (यू.टी.सी.एस.)	
4.	निदेशक, समाज कल्याण	
5.	निदेशक, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा	
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
7.	श्रम आयुक्त	
8.	आयुक्त (उत्पादन शुल्क और मनोरंजन)	
9.	अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)	
10.	अपर आयुक्त, विक्रय कर	
11.	निदेशक, कृषि विपणन	
12.	अपर सचिव (शिक्षा)	
13.	अपर सचिव (वित्त)	
14.	मुख्यमंत्री के सचिव	

	लक्षद्वीप	
1.	कलेक्टर-कम-विकास आयुक्त	
1.	पांडिचेरी	
2.	सरकार के सचिव	
3.	स्थानिक आयुक्त	
4.	उप-राज्यपाल के सचिव	
	असम-मेघालय	
	असम	
1.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	
2.	उप आयुक्त	
3.	सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव /उप सरकार के सचिव	
4.	निदेशक, मूल्यांकन और निगरानी	
5.	मुख्यमंत्री के सचिव	
6.	आयुक्त, परिवहन	
7.	राज्यपाल के सचिव	
8.	निदेशक, उद्योग	
9.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
10.	निदेशक, भूमि रिकार्ड	
11.	आयुक्त, उत्पादन शुल्क	
12.	आयुक्त, कर	
13.	निदेशक, पंचायत और ग्रामीण विकास	
14.	निदेशक, प्रशिक्षण और प्रधानाचार्य, असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	
15.	राज्य जाँच अधिकारी, विभागीय कार्यवाही	
16.	परियोजना निदेशक, आई.आर.डी.ए.पी./अपर उपायुक्त	
17.	श्रम आयुक्त	
	मेघालय	
1.	सचिव/अपर सचिव /संयुक्त सचिव /उप सरकार के सचिव	
2.	विशेष राज्यपाल के सचिव	
3.	आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	
4.	निदेशक, आपूर्ति और व्यापार	
5.	निदेशक, सी. और आर.डी.	
6.	उपायुक्त	

7.	आयुक्त, कर	
8.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
9.	जिला योजना अधिकारी/अपर उप आयुक्त	
	बिहार	
1.	विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	
2.	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट	
3.	व्यवस्थापन अधिकारी/डी.डी.सी.-सह-सी.ई.ओ. जिला बोर्ड	
4.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
5.	सचिव, राजस्व बोर्ड	
6.	निदेशक, भूमि रिकार्ड और सर्वेक्षण	
7.	महानिरीक्षण, कारागार	
8.	श्रम आयुक्त	
9.	निदेशक, पंचायती राज	
10.	निदेशक, उद्योग	
11.	निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार	
12.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	
13.	निदेशक, कल्याण	
14.	राज्य परिवहन आयुक्त	
	छत्तीसगढ़	
1.	कलेक्टर	
2.	कार्यपालक निदेशक, डी.आर.डी.ए. और पदेन, सी.ई.ओ., जिला पंचायत	
3.	अपर कलेक्टर	
4.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, सरकार	
5.	निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	
6.	सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग	
7.	निदेशक सार्वजनिक अनुदेश	
8.	निदेशक, महिला और बाल विकास	
9.	निदेशक, भूमि रिकार्ड	
10.	निदेशक, शहरी प्रशासन	
11.	निदेशक, पंचायत और सामाजिक कल्याण	
12.	निदेशक, कृषि	

	गुजरात	
1.	मुख्यमंत्री के सचिव	
2.	अपर/संयुक्त /उप सरकार के सचिव	
3.	कलेक्टर	
4.	जिला विकास अधिकारी	
5.	निदेशक, नगरपालिका	
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
7.	श्रम आयुक्त	
8.	आयुक्त, मनोरंजन कर	
9.	निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण	
10.	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	
11.	निदेशक, समाज कल्याण	
12.	निदेशक, खाद्य	
13.	अपर आयुक्त, उद्योग	
14.	अपर विकास आयुक्त	
15.	अपर आयुक्त, विक्रय कर	
	हरियाणा	
1.	संयुक्त/उप सरकार के सचिव	
2.	श्रम आयुक्त	
3.	निदेशक, खाद्य और आपूर्ति	
4.	निदेशक, जन संपर्क, शिकायत और सांस्कृति कार्य	
5.	निदेशक, आतिथ्य और पर्यटन	
6.	निदेशक, चकबंदी, भूमि रिकार्ड और विशेष कलेक्टर	
7.	निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	
8.	निदेशक, महिला और बाल विकास	
9.	निदेशक, उद्योग प्रशिक्षण	
10.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	
11.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	
12.	निदेशक, पर्यावरण	
13.	निदेशक, खेल	
14.	निदेशक, विकास और पंचायत	
15.	निदेशक, ग्रामीण विकास और संस्थागत वित्त	

16.	निदेशक, आपूर्ति और निवर्तन	
17.	निदेशक, स्थानिक निकाय	
18.	उप आयुक्त	
19.	अपर वाणिज्य-कर आयुक्त	
20.	अपर उप आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अपर कलेक्टर	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सरकार के सचिव	
2.	सचिव, लोक सेवा आयोग	
3.	निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	
4.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
5.	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	
6.	निदेशक, पंचायती राज-सह-निदेशक, ग्रामीण एकीकृत विकास	
7.	श्रम आयुक्त और निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण	
8.	निदेशक, परिवहन	
9.	निदेशक, पर्यटन	
10.	निदेशक, सतर्कता	
11.	व्यवस्थापन अधिकारी	
12.	उपायुक्त	
13.	आयुक्त, विभागीय जॉच	
14.	अपर उप आयुक्त	
15.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
16.	अपर निदेशक, उद्योग	
17.	निदेशक, भूमि रिकार्ड	
18.	निदेशक, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उद्यम	
19.	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	
	जम्मू और कश्मीर	
1.	संयुक्त वित्त आयुक्त (कृषि भूमि संबंधी सुधार)	
2.	विक्रय कर आयुक्त	
3.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	
4.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
5.	निदेशक, पर्यटन	

6.	निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	
7.	उपायुक्त	
8.	निदेशक, खाद्य और आपूर्ति	
9.	सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव	
10.	मुख्यमंत्री के सचिव	
11.	राज्यपाल के सचिव	
12.	श्रम आयुक्त	
13.	मुख्य निर्वाचक अधिकारी	
14.	व्यवस्थापन आयुक्त	
15.	आयुक्त, विभागीय जाँच	
16.	अपर उपायुक्त	
	झारखण्ड	
1.	विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	
2.	जनजाति विकास आयुक्त	
	निदेशक, उद्योग	
3.	आई.जी. कारागार	
4.	आई.जी. पंजीकरण	
5.	राज्य परिवहन आयुक्त	
6.	श्रम आयुक्त	
7.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
8.	उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त	
9.	व्यवस्थापन अधिकारी/डी.डी.सी.	
10.	आयुक्त, (वाणिज्य-कर)	
11.	निदेशक, पंचायती राज	
12.	निदेशक, भूमि अधिग्रहण और भूमि रिकार्ड	
	कर्नाटक	
1.	अपर/संयुक्त/उप सरकार के सचिव	
2.	निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग	
3.	सचिव कर्नाटक लोक सेवा आयोग	
4.	निदेशक, ग्रामीण अवसंरचना और ई/ओ ए.एस./जे.एस./डी.एस. सरकार, आर.डी.पी.आर.	
5.	अपर/संयुक्त निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	

6.	संयुक्त/अपर आयुक्त (वाणिज्य-कर)	
7.	निदेशक, कृषि विपणन	
8.	निदेशक, एस.ई.पी. और ई/ओ अपर/संयुक्त/उप सरकार के सचिव, ए.डी.पी.आर.	
9.	निदेशक, पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा	
10.	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	
11.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	
12.	निदेशक, परियोजना योजना और निगरानी एकांक और ई/ओ अपर/संयुक्त/उप सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग	
13.	अपर स्थानिक आयुक्त	
14.	अपर/संयुक्त आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	
15.	निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई अभिकरण और ई/ओ अपर/संयुक्त सरकार के सचिव, आई.डी.पी.आर.	
16.	उप आयुक्त/वरिष्ठ सहायक आयुक्त/विशेष उप आयुक्त/राजपत्रित सहायक मंडल आयुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद	
17.	आयुक्त, धार्मिक और धर्मार्थ दान और ई/ओ अपर/संयुक्त/उप सचिव, सरकार, राजस्व विभाग	
	केरल	
1.	विशेष सचिव/अपर/संयुक्त/उप सरकार के सचिव	
2.	संयुक्त/उप आयुक्त	
3.	सचिव, भूमि बोर्ड	
4.	निदेशक, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान	
5.	महानिरीक्षक, पंजीकरण	
6.	निदेशक, मछली पालन	
7.	निदेशक, पंचायत	
8.	निदेशक, नगरपालिका	
9.	निदेशक, जन संपर्क	
10.	निदेशक, पर्यटन	
11.	निदेशक, खेल और युवा कार्य	
12.	निदेशक, समाज कल्याण	
13.	निदेशक, अनुसूचित जाति और विकास विभाग	
14.	श्रम आयुक्त	
15.	निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण	
16.	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	

17.	जिला कलेक्टर	
18.	निदेशक, पुनर्वास	
19.	अपर निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	
20.	निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि रिकार्ड	
21.	निदेशक अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	
22.	जिला योजना अधिकारी/महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए./इलायची व्यवस्थापन अधिकारी/उप-कलेक्टर ग्रेड-I	
	मध्य प्रदेश	
1.	कलेक्टर	
2.	अपर आयुक्त, राजस्व	
3.	कार्यपालक निदेशक, डी.आर.डी.ए. और पदेन, सी.ई.ओ., जिला पंचायत	
4.	अपर उप सचिव	
5.	निदेशक रोजगार और प्रशिक्षण	
6.	निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	
7.	समिति लोक सेवा आयोग	
8.	अपर आयुक्त, विक्रय कर	
9.	अपर आयुक्त, जनजाति विकास	
10.	निदेशक कृषि विपणन	
11.	निदेशक, संस्थागत वित्त	
12.	निदेशक, शहरी प्रशासन	
13.	निदेशक, पंचायत और सामाजिक कल्याण	
	महाराष्ट्र	
1.	संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव	
2.	कलेक्टर	
3.	कलेक्टर बम्बई उपनगरीय जिला	
4.	अपर कलेक्टर	
5.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्	
6.	निदेशक, नागरिक आपूर्ति (भण्डारण और संचालन)	
7.	उप निदेशक, भूमि रिकार्ड	
8.	महानिरीक्षक, पंजीकरण	
9.	अपर आयुक्त, विक्रय कर	
10.	अपर आयुक्त, उद्योग	



11.	उप आयुक्त, विक्रय कर	
12.	निदेशक, समाज कल्याण	
13.	अपर आयुक्त	
14.	निदेशक, हथकरघा, मशीन-करघा और सहकारी वस्त्र	
15.	निदेशक, रोजगार	
16.	निदेशक, खेल और युवा कार्य	
17.	नियंत्रक, राशन	
18.	अपर आयुक्त, जनजाति उप-योजना	
19.	निदेशक, अल्प बचत	
	मणिपुर-त्रिपुरा	
	मणिपुर	
1.	सरकार के सचिव	
2.	मुख्यमंत्री के सचिव	
3.	सचिव, लोक सेवा आयोग	
4.	विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	
5.	उपायुक्त	
6.	उपायुक्त, पर्वी इम्फाल	
7.	जिला योजना अधिकारी-सह-अपर उप आयुक्त -सह- अपर जिला मजिस्ट्रेट	
8.	आयुक्त विभागीय जाँच	
9.	आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	
10.	आयुक्त, कर	
11.	निदेशक, सतर्कता	
12.	निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	
13.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
14.	निदेशक, भूमि रिकार्ड और व्यवस्थापन	
15.	निदेशक, पर्यटन	
16.	निदेशक, सूचना और जन संपर्क	
17.	निदेशक, वाणिज्य और उद्योग	
18.	निदेशक, परिवहन	
19.	निदेशक, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास विभाग	
20.	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास	
21.	निदेशक, युवा कार्य और खेल	

	त्रिपुरा	
1.	सरकार के सचिव	
2.	मुख्यमंत्री के सचिव	
3.	सचिव, लोक सेवा आयोग	
4.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सरकार के सचिव	
5.	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	
6.	अपर जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	
7.	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	
8.	निदेशक, विद्यालय शिक्षा	
9.	निदेशक, सतर्कता	
10.	निदेशक, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा	
11.	निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	
12.	निदेशक, भूमि रिकार्ड और व्यवस्थापन	
13.	निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक कार्य और पर्यटन	
14.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
15.	निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण	
16.	निदेशक, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	
17.	श्रम आयुक्त	
18.	आयुक्त, कर और उत्पाद-शुल्क	
19.	आयुक्त विभागीय जाँच	
20.	निदेशक, राज्य लोक प्रशासन संस्थान और ग्रामीण विकास	
21.	निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	
22.	निदेशक, युवा कार्य और खेल	
23.	निदेशक, सूचना और प्रौद्योगिकी	
24.	निदेशक, कथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन	
	नागालैंड	
1.	सचिव	
2.	अपर/संयुक्त/उप सरकार के सचिव	
3.	उप आयुक्त	
4.	अपर उप आयुक्त	
	उड़ीसा	
1.	सचिव/अपर सरकार के सचिव	

2.	संयुक्त/उप सरकार के सचिव	
3.	सचिव, राजस्व बोर्ड	
4.	मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	
5.	अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-कलेक्टर, गेड-1/व्यवस्थापन अधिकारी/उप निदेशक, चकबंदी/महा प्रबंधक, डी.आई.जी./परियोजना प्रशासन, आई.टी.डी.ए./परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
7.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
8.	निदेशक, हरिजन और जनजाति कल्याण	
9.	निदेशक, पंचायती राज	
10.	निदेशक, उद्योग	
11.	अपर निदेशक, उद्योग	
12.	निदेशक, रोजगार	
13.	महानिरीक्षक, पंजीकरण और उत्पाद-शुल्क आयुक्त	
14.	श्रम आयुक्त	
15.	निदेशक, पर्यटन	
16.	निदेशक, वस्त्र	
17.	निदेशक, निर्यात संवर्धन और विपणन	
18.	निदेशक, सामाजिक कल्याण	
19.	निदेशक, विशेष परियोजना	
	पंजाब	
1.	अपर/संयुक्त सरकार के सचिव	
2.	निदेशक, सूचना और जन संपर्क	
3.	राज्य परिवहन आयुक्त	
4.	निदेशक, राज्य परिवहन	
5.	निदेशक, उद्योग	
6.	निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत	
7.	निदेशक, महिला विकास और बाल विकास	
8.	निदेशक, भूमि रिकार्ड और व्यवस्थापन, चकबंदी और भूमि अधिग्रहण	
9.	निदेशक, शिकायत और पेंशन	
10.	निदेशक, स्थानीय सरकार	
11.	श्रम आयुक्त और निदेशक, रोजगार	
12.	निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	

13.	अपर निदेशक, उद्योग	
14.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
15.	अपर उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त	
16.	उपायुक्त	
17.	अपर उप आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अपर उप आयुक्त (विकास)	
	राजस्थान	
1.	विशेष सरकार के सचिव	
2.	उप सरकार के सचिव	
3.	व्यवस्थापन आयुक्त	
4.	निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज	
5.	कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	
6.	निदेशक, जलसंभर	
7.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	
8.	निदेशक, अल्प बचत	
9.	निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि	
10.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्	
11.	अपर आयुक्त, कर आयुक्त	
12.	निदेशक, जलसंभर विकास और भूमि संरक्षण	
13.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
14.	रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड	
15.	अपर आयुक्त, खाद्य	
16.	निदेशक, सूचना और जन संपर्क	
17.	निदेशक, पर्यटन	
18.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी	
19.	महानिरीक्षक पंजीयन और स्टाम्प	
20.	सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग	
21.	निदेशक, सामाजिक कल्याण	
22.	निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग	
	सिक्किम	
1.	सरकार के सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	
2.	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	

	तमिलनाडु	
1.	सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	
2.	निदेशक, आदी द्रविडार और जनजाति कल्याण	
3.	उप आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/अपर संयुक्त आयुक्त	
4.	संयुक्त आयुक्त, नागरिक आपूर्ति मुख्यालय	
5.	महानिरीक्षक, पंजीयन	
6.	निदेशक, कृषि	
7.	निदेशक, सर्वेक्षण और व्यवस्थापन	
8.	निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण	
9.	निदेशक, पुनर्वास	
10.	निदेशक, हथकरघा और वस्त्र	
11.	निदेशक, मछलीपालन	
12.	निदेशक, अल्प बचत और लॉटरी	
13.	निदेशक, लेखन-सामग्री और मुद्रण	
14.	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	
15.	उप आयुक्त, वाणिज्य-कर	
16.	अपर आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य	
17.	कलेक्टर	
18.	व्यवस्थापन अधिकारी	
19.	निदेशक, भूमि सुधार	
20.	अपर निदेशक, कृषि	
21.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
22.	सचिव, राज्य चुनाव आयोग	
23.	निदेशक, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज	
24.	निदेशक, शहर और देश योजना	
25.	निदेशक, कृषि विपणन	
26.	निदेशक, उद्यान-विज्ञान और वृक्षारोपण	
27.	निदेशक, खजाना और लेखा	
28.	निदेशक, सांख्यिकी	
29.	निदेशक, विश्विद्यालयी शिक्षा	
30.	निदेशक, भू-विज्ञान और खनन	
31.	निदेशक, सूचना और जन संपर्क	
32.	निदेशक, रेशम उत्पादन	

33.	निदेशक, समाज कल्याण	
34.	उप-कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास)	
35.	सचिव, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग	
36.	आयुक्त, हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ दान	
37.	आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही (मदुरै, कोयम्बटूर)	
38.	अपर निदेशक, समाज कल्याण	
39.	निदेशक, पर्यटन	
40.	परीक्षा नियंत्रक, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग	
41.	उप सचिव, मध्यांतर आहार कार्यक्रम	
42.	निदेशक, शहरी भूमि परिसीमन	
43.	संयुक्त आयुक्त, भूमि प्रशासन	
44.	मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव	
45.	उप मुख्यमंत्री के सचिव	
46.	आयुक्त, सरकारी डाटा केन्द्र	
	उत्तरांचल	
1.	आयुक्त और निदेशक उद्योग	
2.	आयुक्त, श्रम और निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार	
3.	निदेशक, संस्कृति और खेल	
4.	परिवहन आयुक्त	
5.	निदेशक, सूचना और सम्पादक, गजट	
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
7.	जिला मजिस्ट्रेट	
8.	अपर सचिव	
9.	मुख्य विकास अधिकारी	
	उत्तर प्रदेश	
1.	जिला मजिस्ट्रेट	
2.	संयुक्त विकास आयुक्त/सी.डी.ओ./अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास	
3.	विशेष सरकार के सचिव	
4.	संयुक्त सरकार के सचिव	
5.	अपर संयुक्त श्रम आयुक्त	
6.	अपर संयुक्त निदेशक, उद्योग	
7.	अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति	

8.	अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास	
9.	अपर/संयुक्त विक्रय कर आयुक्त	
10.	निदेशक, पंचायत	
11.	निदेशक, सूचना	
12.	निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार	
13.	निदेशक, सामाजिक कल्याण	
14.	सचिव, लोक सेवा आयोग	
15.	निदेशक, शहरी भूमि परिसीमन	
16.	राहत आयुक्त	
17.	निदेशक, स्थानिक निकाय	
18.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक	
19.	निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
20.	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
21.	उप भूमि सुधार आयुक्त	
22.	निदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो और संयुक्त/विशेष सरकार के सचिव	
23.	निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.	
24.	अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	
25.	अपर स्थानिक आयुक्त	
	पश्चिम बंगाल	
1.	निदेशक, भूमि रिकार्ड और सर्वेक्षण	
2.	निदेशक, सार्वजनिक वहन विभाग	
3.	संयुक्त सरकार के सचिव	
4.	निदेशक, कुटीर और लघु उद्योग	
5.	निदेशक, मूल्यांकन, विकास और योजना विभाग	
6.	निदेशक, राशन	
7.	निदेशक, जिला वितरण वसूली और आपूर्ति	
8.	निदेशक, स्थानिक निकाय और पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय सरकार और शहरी विकास विभाग	
9.	सचिव, सतर्कता आयोग	
10.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	
11.	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	
12.	अपर जिला मजिस्ट्रेट/व्यवस्थापन अधिकारी	

13.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (डी.एल.एल.आर.ओ.)	
14.	भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, कलकत्ता	
15.	निदेशक, रोजगार	
16.	निदेशक, उपभोक्ता माल	
17.	निदेशक, मछली पालन	
18.	निदेशक, ई.एस.आई.	
19.	निदेशक, रेशन - उत्पादन	
20.	प्रधान निदेशक, एस.आई.पी.ए.आर.डी., कल्याणी	
21.	आयुक्त, कृषि आय कर	
22.	सलाहकार, उद्योग	
23.	निदेशक, उद्योग	
24.	प्रधान सचिव, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्	
25.	सचिव, के.एम.डी.ए.	
26.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डब्ल्यू.बी.आई.आई.डी.सी.	

ग-केन्द्रीय सरकार के अधीन पद जब सेवा के सदस्य द्वारा धारित किए जाते हैं।

पद का नाम	वेतनमान	केन्द्रीय भत्ता (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति)
(1) मंत्रिमंडल सचिव	30,000/- रु. (नीयत)	---
(2) सचिव, भारत सरकार/विशेष सचिव, भारत सरकार	26,000/- रु. (नीयत)	---
(3) अपर सचिव, भारत सरकार	22,400-525-24,500/- रु.	---
(4) संयुक्त सचिव, भारत सरकार	18,400-500-22,400/- रु.	---
(5) निदेशक, भारत सरकार	चयन श्रेणी (15,100-400-18,300/- रु.)	अधिकतम एक हजार रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन श्रेणी का पंद्रह प्रतिशत



<p>(6) उप-सचिव, भारत सरकार</p>	<p>(i) चयन श्रेणी (15,100-400-18,300/- रु.)</p> <p>या</p> <p>(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (12,750-375-16,500/- रु.)</p>	<p>अधिकतम एक हजार रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन श्रेणी का पंद्रह प्रतिशत</p> <p>अधिकतम एक हजार रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन श्रेणी का पंद्रह प्रतिशत और आगे इसके अधीन कि केन्द्रीय भत्ता (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) सहित वेतन, वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।</p>
<p>(7) अवर सचिव, भारत सरकार</p>	<p>(i) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (12,750-375-16,500/- रु.)</p> <p>या</p> <p>(ii) ज्येष्ठकाल समय वेतनमान (10,650-325-15,850/- रु.)</p>	<p>अधिकतम आठ सौ रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन श्रेणी का पंद्रह प्रतिशत और आगे इसके अधीन कि केन्द्रीय भत्ता (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) सहित वेतन, वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।</p> <p>अधिकतम आठ सौ रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन श्रेणी का पंद्रह प्रतिशत और आगे इसके अधीन कि केन्द्रीय भत्ता (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) सहित वेतन, वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।</p>

टिप्पण - इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता केवल प्रतिनियुक्ति की सामान्य पदावधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य को, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुज्ञेय होगा।

[फा. सं. 20011/1/2005-अ.भा.से.-II]

आर. के. गुप्ता, डेस्क अधिकारी

# **MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2007

**G.S.R. 213(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in supersession of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely:—

### **1. Short title and commencement :—**

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except the second proviso to sub-rule (1) of rule 3 and proviso to clause (i) of sub-rule (2) of rule 3 which shall come into effect from 1-4-2007.

### **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) 'benchmark score' shall mean the minimum numerical weighted mean score arrived at for overall grading above which an officer shall be regarded as fit for promotion or empanelment, as the case may be, to the next higher grade;
- (b) 'cadre' and 'cadre posts' shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954;
- (c) 'departmental examination' means such examination as may be prescribed by the State Government from time to time for members of the Service allotted to the cadre of the State or posted to that State for training;
- (d) 'direct recruit' means a person appointed to the Indian Administrative Service in accordance with rule 7 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954;
- (e) 'grade pay' means the basic pay drawn by a member of the Service in the grade in which he is appointed substantively;
- (f) 'lien' means the title of a member of the Service to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post, including a tenure post, to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.
- (g) 'member of the Service' means a member of the Indian Administrative Service;
- (h) 'Non-State Civil Service' shall have the meaning as assigned to it in sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954;

- (i) 'Officer appointed by selection' means an officer appointed to the Indian Administrative Service in accordance with sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954;
- (j) 'Officiation' means an officer performing the duties of a post on which another member of the Service holds a lien and it includes an officer appointed by the Government in officiating capacity in a vacant post in which no other member of the Service holds the lien;
- (k) 'personal pay' means additional pay granted to a member of the Service -
  - (a) to save him from a loss in his substantive pay in respect of a permanent post other than a tenure post due to a revision of pay or due to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure; or
  - (b) in exceptional circumstances, on other personal considerations;
- (l) 'promoted officer' means an officer appointed to the Indian Administrative Service by promotion from a State Civil Service in accordance with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954;
- (m) 'promotion' means appointment of a member of the Service to the next higher grade over the one in which he is serving at the relevant time;
- (n) 'Schedule' means a Schedule appended to these rules;
- (o) 'Service' means the Indian Administrative Service;
- (p) 'State' means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union Territory;
- (q) 'State Cadre' and 'Joint Cadre' have the meanings respectively assigned to them in the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954;
- (r) 'State Civil Service' shall have the meaning assigned to it in the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954;
- (s) 'State Government concerned' in relation to a Joint Cadre means the Joint Cadre Authority.

**Note 1:** The benchmark score shall be notified by the State Government for promotion within the cadre and by the Central Government for the purpose of empanelment. Any revision of benchmarks by the Government shall have prospective effect;

**Note 2:** The junior-most person(s) in the grade will, however, be liable to be reverted to the lower grade if the number of members of the Service entitled to hold the regular posts is more than the number of posts available in that grade.

### **3. Scale of pay and appointment in these grades.—**

- (1) The scale of pay admissible to a member of the Service and the dates with effect from which the said scale shall be deemed to have come into force, shall be as follows:—

**Junior Scale - Rs.8000-275-13500** (with effect from the 1st day of January, 1996).

**Senior Scale - (i) Time Scale - Rs.10650-325-15850** (with effect from the 1st day of January, 1996);

(ii) **Junior Administrative Grade - Rs.12750-375-16500** (non-functional) (with effect from the 1st day of January, 1996);

(iii) **Selection Grade - Rs.15100-400-18300/-** (with effect from the 1st day of January, 1996);

**Super Time Scale - (a) Rs.18400-500-22400/-** (with effect from the 1st day of January, 1996)

**Above Super Time Scale - (i) Rs. 22400-525-24500;**

(ii) Rs. 26000; (fixed)

(iii) Rs. 30000; (fixed) (for the post of Cabinet Secretary in Government of India only).

(with effect from the 1st day of January, 1996).

**Note—**Appointment of a member of the Service to the Time Scale and above shall be regulated as per the provisions in the Guidelines regarding promotion to various grades in the Indian Administrative Service:

Provided that a member of the Service shall become eligible for being appointed to the senior time scale on his completion of four years of service, subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 6A of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 and to the Junior Administrative Grade on completion of nine years of service, to the Selection Grade on completion of thirteen years of service and to the Super Time Scale on completion of sixteen years of service :

Provided further that a member of the service shall be appointed to the Junior Administrative Grade only after he has completed phase III mandatory Mid Career Training as prescribed.

**Note 1:** The four years, nine years, thirteen years and sixteen year of service in this rule shall be calculated from the year of allotment assigned to him under rule 3 of the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1987.

**Note 2 :** The period of extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate or considered by the State Government concerned to have been taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for prosecuting studies, which are in public interest and for which Study Leave could otherwise be admissible under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960, shall be excluded for the purpose of calculating the eligibility period of service required for appointment in these grades:

Provided also that a member of Service may opt to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale. The option shall be exercised in

accordance with such orders as may be issued by the Central Government in this behalf.

**Explanation 1** - The option to retain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

**Explanation 2** - The said option shall not be admissible to any person appointed to the Service on or after the 1st day of January, 1996 and he shall be allowed pay only in the revised scale.

**Explanation 3** - Where a member of the Service exercises an option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force whichever is higher.

(2)(i) Appointment to the Selection Grade and to posts carrying pay above this grade in the Indian Administrative Service shall be made by selection on merit, as per criteria that may be prescribed by the Central Government, with due regard to seniority :

Provided that a member of the Service shall be appointed to the Super Time Scale only after he has completed phase IV mandatory Mid Career Training as prescribed.

(ii) Appointment of a member of the Service in the scales of Selection Grade and above shall be subject to availability of vacancies in these grades and for this purpose, it shall be mandatory upon the State Cadres or the Joint Cadre Authorities, as the case may be, to seek prior concurrence of the Central Government on the number of available vacancies in each grade.

(iii) The Central Government shall accord such concurrence within a period of thirty days from the date of receipt of such references and if the Central Government does not accord concurrence within a period of said thirty days, the concurrence on availability of vacancies shall be deemed to have been accorded. The position emanating as referred to this clause shall be placed before the Screening Committee at the time it meets to consider promotion in these grades.

(iv) A member of the Service shall be entitled to draw pay in the scales of Selection Grade and above only on appointment to these grades.

**3A. Fixation of pay in the revised scales.** The initial pay of a member of the Service who opts or deemed to have opted in accordance with these rules, to be governed by the revised scale on and from the 1st day of January,

1996 or from a later date, which shall be re-fixed as from that date separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:—

(A) in the cases of all members of the Service,—

- (i) an amount representing forty per cent of the basic pay in the existing scale shall be added to the 'existing emoluments' of the member of the Service;
- (ii) After the existing emoluments have been so increased, the pay shall thereafter be fixed in the revised scale at the stage next above the amount computed:

Provided that —

- (a) if the minimum of the revised scale is more than the amount so arrived at, the pay shall be fixed at the minimum of the revised scale;
- (b) if the amount so arrived at is more than the maximum of the revised scale, the pay shall be fixed at the maximum of that scale :

Provided further that where in the fixation of pay, the pay of a member of the Service drawing pay at more than four consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is, gets fixed in the revised scale at the same stage, the pay in the revised scale of such member of the Service who is drawing pay beyond the first four consecutive stages in the existing scale shall be stepped up to the stage where such bunching occurs by the grant of increments in the revised scale in the following manner, namely:—

- (a) for a member of the Service drawing pay from the 5th up to the 8th stage in the existing scale, by one increment
- (b) for a member of the Service drawing pay from the 9th up to the 12th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 8th stage, by two increments
- (c) for a member of the Service drawing pay from the 13th up to the 16th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 12th stage, by three increments

If by stepping up of the pay as referred in this rule, the pay of a member of the Service gets fixed at the stage in the revised scale which is higher than the stage in the revised scale at which the pay of a member of the Service who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the later shall also be stepped up to the extent by which it falls short of that of the former.

Provided also that the fixation of pay made shall ensure that every member of the Service shall get at least one increment in the revised scale of pay for every three increments (inclusive of stagnation increments), if any, in

the existing scale of pay.

**Explanation :—**For the purposes of this clause, "existing emoluments" shall include—

- (a) the basic pay in the existing scale;
- (b) dearness allowance appropriate to the basic pay admissible at index average 1510 (1960 = 100); and
- (c) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale;

(B) in the case of a member of the Service who is in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing scale, such as personal pay for promoting small family norms, Central (deputation on tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised scale with corresponding allowance or pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) and in such cases, the allowance at the new rate as recommended, shall be drawn in addition to pay in the revised scale of pay.

**Note 1:** Where the increment of a member of the Service falls on 1st day of January, 1996, he shall have an option to draw the increment in the existing scale or the revised scale.

**Note 2:** Where a member of the Service is on leave other than the Study Leave granted under the All India Services (Study Leave) Regulations, 1960, on the 1st day of January, 1996, he shall become entitled to pay in the revised scale of pay from the date he resumes duty and in case of a member of the Service under suspension, he shall continue to draw subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised scale of pay will be subject to final order on the pending disciplinary proceedings.

**Note 3:** Where the existing emoluments as calculated in accordance with clause (A) or clause (B), as the case may be, exceed the revised emoluments in the case of any member of the Service, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note 4:** Where in the fixation of pay under these rules, pay of a member of the Service who in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 1996, more pay than another member of the Service junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised scale at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised scale as that of the junior.

**Note 5:** Where a member of the Service is in receipt of personal pay on the 1st day of January, 1996, which together with his existing emoluments as calculated in accordance with clause (A) or clause (B), as the case may be, exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such member of the Service as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note 6:** Where a senior member of the Service promoted to a higher post before the 1st day of January, 1996 draws less pay in the revised scale than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 1996, the pay of the senior member of the Service shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and the stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior member of the Service subject to the fulfilment of the following conditions, namely:—

- (a) both the junior and the senior member of the Service shall belong to the same cadre and the post in which they have been promoted shall be identical in the same cadre;
- (b) the pre-revised and revised scale of pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay shall be identical;
- (c) the senior member of the Service at the time of promotion has been drawing equal or more pay than the junior; and
- (d) the anomaly shall be directly as a result of the application of the provisions of this sub-rule. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provisions of this rule need not be invoked to step up the pay of the senior member of the Service.

**Note 7:** The order relating to re-fixation of the pay of the senior member of the Service in accordance with the above provisions shall be issued under the relevant rules and the senior member of the Service shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

**Note 8:** Subject to the provisions of sub-rule (1), if the pay as fixed in the officiating post under this sub-rule is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the stage next above the substantive pay.

**Note 9:** In the case of a member of the Service who is in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya and such other examinations under the Hindi Teaching Scheme prior to the 1st day of January, 1996, while the personal pay shall not be taken into account for the purpose of fixation of initial pay in the revised scale, he shall continue to draw personal pay after fixation of his pay in the revised scale on and from the 1st day of January, 1996 or subsequently for the period for which he would have drawn it but for the fixation of his pay in the revised scale and the quantum of such personal pay shall be paid at the appropriate rate of increment in the revised scale from the date of fixation of pay for the period for which the member of the Service would have continued to draw it.

**Explanation:—** For the purposes of this rule, “appropriate rate of increment in the revised scale” means the amount of increment admissible at and immediately beyond the stage at which the pay of the member of the Service is fixed in the revised scale.

(C) Fixation of pay in the revised scale subsequent to the 1st day of January, 1996—Where a member of the Service continues to draw his pay in the existing scale and opts for revised scale from a date later than the 1st day of January, 1996, his pay from the later date in the revised scale shall be fixed under these rules and for this purpose his pay in the existing scale shall be the same as of existing emoluments as calculated in accordance with clause (A) or clause (B), as the case may be, subject to the conditions that the basic pay to be taken into account for calculation of those emoluments shall be the basic pay on the later date and where the member of the Service is in receipt of special allowance, his pay shall be fixed after deducting from those emoluments an amount equal to the special allowance at the revised rates appropriate to the emoluments so calculated.

**4. Fixation of initial pay.** (1) The initial pay of a direct recruit shall be fixed at the minimum of the Junior Scale :

Provided that, if a direct recruit holds a lien, or would hold the lien, had his lien not been suspended on a permanent post, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Indian Administrative Service, his initial pay shall be regulated in following manner, namely:—

- (a) he shall, during the period of probation, draw the pay of the permanent post, if it is more than the minimum of the Junior Scale and on confirmation in the Indian Administrative Service;
- (b) if he was holding a Class I post before appointment to the Indian Administrative Service, his pay shall be fixed at the same stage as the pay in the Class I post if there be such a stage in the Junior Scale admissible to a member of the Service, or at the next lower stage, if there is no such stage in the Junior Scale admissible to a member of the Service and where the pay so fixed in the Indian Administrative Service is less than his pay in the Class I post, he shall be allowed the difference as personal pay to be absorbed in future increments; and
- (c) if he was holding a post lower than a Class I post, his pay shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay had accrued;
- (d) he shall however, cease to earn any increments in the Junior Scale, until, having regard to his length of service, he becomes entitled to a higher pay:

Provided further that he shall draw the pay admissible under rule 7 if that is more than the pay referred to in the preceding proviso.

(2) The pay of a member of the Service in the Junior Scale shall, on appointment to a post in the Senior Time Scale, be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in lower scale by one increment at the stage at which such pay accrued (or by an amount equal to the last increment in the lower scale if he was drawing pay at the maximum of the lower scale) or the minimum of the higher scale, whichever is higher.

(3) The initial pay of a State Civil Service officer, on his appointment to the Service or on appointment in a cadre post in an officiating capacity in accordance with rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, as the case may be, shall be fixed as per the principles laid down in Schedule I. Further pay and incremental benefits shall accrue to him under the other relevant provisions.

(4) The initial pay of an officer appointed by selection to the Service or on appointment to a cadre post in an officiating capacity, in accordance with rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, as the case may be, shall be fixed by the Central Government in consultation with the State Government concerned, in the manner specified in Schedule I. Further pay and incremental benefits shall accrue to him under the other relevant provisions.

(5) The pay of a member of the Service in the Senior Time Scale shall, on appointment to the Junior Administrative Grade, be fixed (a) at the stage which is equal to his pay in the Senior Time Scale or if there is no such stage, at the stage next above that pay, or (b) the minimum of the Junior Administrative Grade, whichever is higher.

(6) The pay of a member of the Service in the Junior Administrative Grade shall, on appointment in the Selection Grade, be fixed in the same manner as in sub-rule (5) above.

(7) The pay of a member of the Service in the Selection Grade, on appointment to the Super Time Scale and in the Super Time Scale, on appointment to the first above Super Time Scale, shall be fixed in the same manner as in sub-rule (2) above.

(8) On promotion from one grade to another in the Service, a member of the Service shall have an option to get his pay fixed in the higher scale either from the date of his promotion in the manner provided in the relevant sub-rule above or from the date on which he subsequently earns an increment in the lower scale. In the latter case, pay on the date of promotion shall first be fixed in the higher scale as per the relevant provisions in cases of promotion in the Junior Administrative Grade/Selection Grade and at the stage above the pay in the lower scale in other cases, with further re-fixation in the manner provided in sub-rule (2) on the date of accrual of the next increment in the lower scale. The date of next increment in such a case shall fall on completion of 12 months' qualifying service from the date the pay is re-fixed on the second

occasion. The option shall be exercised within one month of the promotion and shall be final.

**5. Regulation of increments.**— (1) Subject to any order passed by the State Government concerned, under rule 5A or rule 6 or rule 7, the increment admissible to a member of the Service appointed under rule 7 or rule 7A of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, shall accrue on the expiry of each year of qualifying service :

Provided that the increments thus falling due shall accrue on the first day of the month in which they would have accrued.

(2) Subject to the provisions of Clauses 2 and 3 of Schedule I, in the case of a promoted officer or an officer appointed by selection, the increments shall accrue on completion of each year of qualifying service from the date his pay has been fixed in accordance with the provisions contained in Schedule I and the same principles shall apply in cases where appointment to the service is preceded by officiation on a cadre post:

Provided that the increments thus falling due shall accrue on the first day of the month in which they would have accrued:

Provided further that for the purpose of calculating one year's service for drawing of increment, broken period of service rendered in a cadre post shall be taken into account.

(3) The next increment of a member of the Service whose pay has been fixed in the revised scale in accordance with rule 3A shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he continued in the existing scale:

Provided that where the pay of a member of the Service is stepped up in accordance with the second proviso or sub-rule (3) of rule 3A, the next increment shall be granted on the date of drawing of increment by the member of the Service with reference to whose pay such stepping up has been allowed:

Provided further that in other cases, the next increment of a member of the Service whose pay is fixed on the 1st day of January, 1996 at the same stage as the one fixed for another member of the Service junior to him in the same cadre and drawing pay at a lower stage than him in the existing scale, shall be granted on the same date as admissible to his junior, if the date of increment of the junior happens to be earlier:

Provided also that in case of a member of the Service who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 1996, the next increment in the revised scale shall be allowed on the 1st day of January, 1996.

(4) All leave except extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate or the State Government concerned is satisfied that the leave have been

taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for prosecuting studies which are in public interest and for which study leave could otherwise be granted under the All India Services (Study Leave) Regulations, 1960, shall count for increment applicable in the scale of pay of a post held by him at the time he proceeded on such leave.

(5) The period of deputation out of India shall also be so counted and the counting of the said period for increments shall be subject to the condition that the member of the Service would have continued to hold that post but for his proceeding on such leave or deputation out of India :

Provided that where the leave is not counted for increment under this rule, it shall have the effect of postponing the next increment to the extent of the period involved.

(6) The increments admissible to a member of the Service in a pay scale specified in sub-rule (1) of rule 3 shall be regulated with reference to the length of his service including broken period of service rendered in that scale of pay and the previous service, if any, shall also count for increment, if it is -

- (i) service in a cadre post; or
- (ii) service in a permanent or temporary post (including a post in a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government) in the said scale or in a higher scale of pay :

Provided that the service in a post outside the cadre, including service in a post under the Central Government, shall count for increment on reversion to the cadre, subject to the following conditions, namely:-

- (a) The member of the Service should have been approved by the Government of the State on the cadre of which he is borne, for appointment to posts in the said scale;
- (b) All his seniors in the cadre, except those regarded as unfit for such appointment, were serving in posts carrying pay in the said scale in which the benefit is to be allowed or in higher posts, and at least one junior was holding a cadre post, or an ex-cadre post within the permissible State Deputation Reserve or the over-utilised State Deputation Reserve permitted by the Central Government, under the Government of the State on the cadre of which he is borne, carrying pay in the said scale; and
- (c) the service shall count from the date on which his junior is so promoted and the benefit shall be limited to the period during which he would have held a post under the Government of the State on the cadre on which he is borne.

(7) A member of the Service, while holding post outside the cadre, including a post under the Central

Government, may be granted proforma promotion to a post in the scale of pay above the time scale of pay specified in rule 3 by the Government of the State on the cadre to which he is borne.

(8) In case of a member of the Service being cleared for proforma promotion in the Super Time Scale and the Above Super Time Scale, the period of service covered by the proforma promotion shall, on his subsequent reversion to the cadre and appointment to a post in the said scale, count towards the initial fixation of pay and increments subject to the following conditions, namely:-

- (i) the member of the Service concerned should have been approved by the State Government for appointment to the said scale during the relevant period;
- (ii) all his seniors (excluding those considered unfit) should have started drawing pay in that scale on or before the date from which the proforma promotion is granted to him;
- (iii) the junior next below the officer (or, if that officer has been passed over for the reason of inefficiency or unsuitability or because he is on leave or serving outside the ordinary line or forgoes promotion on his own volition to that grade, the officer next junior to him not so passed over) should also have started drawing pay in that scale from that date and his appointment thereto not being fortuitous; and
- (iv) the benefit should be allowed on 'one for one' basis.

(9) When a member of the Service holds an ex-cadre post in a time scale of pay identical with the time scale of pay of an ex-cadre post held by him on an earlier occasion, his initial pay in the latter ex-cadre post shall not be less than the pay which he drew on the previous occasion and he shall count the period during which he drew that pay on such last and on any previous occasion for increment in the stage of the scale equivalent to that pay and the service so rendered shall, on his reversion to the cadre, count towards initial fixation of pay to the extent and subject to the conditions stipulated in sub-rule (6).

(10) Where a member of the Service is on leave other than the study leave granted under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960, on the date on which an increment becomes due, he shall get the benefit of the same, if otherwise admissible under the rules, from the date he resumes duty but it does not postpone his normal date of increment in future.

(11) No member of the service shall be eligible for drawing increment after completion of 28 years of service unless he completed the Phase V of the mandatory Mid Career Training programme as prescribed.

**5A. Stagnation increments.**—A member of the Service drawing pay in the Junior Scale or Senior Scale or

Super Time Scale shall be eligible for one increment equivalent to the last rate of increment, for every two years of service rendered after reaching the maximum of that scale, subject to a maximum of three increments.

**6. Withholding of increments.** The State Government may withhold, for such time as it may direct, an increment due to any direct recruit or to any non-State Civil Service officer appointed to the Indian Administrative Service, who fails to pass the departmental examination or examinations within such time as the State Government may by general or special order prescribe, but the withholding of such increments shall have no cumulative effect.

**7. Grant of advance increments.** Notwithstanding anything contained in rule 13 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the State Government shall sanction the second and third increments due to a direct recruit as soon as he passes the prescribed departmental examination or examinations irrespective of the length of service, after which he shall be entitled to draw pay at the rate corresponding to his position in the time scale :

Provided that the third increment under this rule shall be granted retrospectively from the date of passing the prescribed departmental examination, or the last of the prescribed departmental examinations, as the case may be, on the successful completion of the probation and confirmation :

Provided further that a direct recruit who has been exempted from appearing for the whole or any part of the departmental examination or examinations, as the case may be, for the reason that he had already passed such examination or examinations or part thereof before he became a member of the Service, shall, for the purpose of this rule, be deemed to have passed the departmental examination or examinations or part thereof, as the case may be, from the date of the earliest such examination, examinations or part thereof, in which he would have appeared, but for the exemption, after he became a member of the Service.

**8. Pay of officers holding posts included in Schedule II.** A member of the Service appointed to hold a post specified in Schedule II shall, for so long as he holds that post, be entitled to draw the pay indicated for that post in the said Schedule plus Special Allowance or Central (Deputation or Future) Allowance, wherever admissible:

Provided that such pay shall not at any time be less than the pay admissible under rules 4 and 5 of these rules.

**9. Pay of members of the Service appointed to posts not included in Schedule II.** (1) No member of the Service shall be appointed to a post other than a post specified in Schedule II, unless the State Government concerned in respect of posts under its control, or the Central Government in respect of posts under its control, as the case may be, make a declaration that the said post is equivalent in status and responsibility to a post specified in the said Schedule.

(2) The pay of a member of the Service on appointment to a post other than a post specified in Schedule II shall be the same as he would have been entitled to, had he been appointed to the post to which the said post is declared equivalent.

(3) For the purpose of this rule, post other than a post specified in Schedule II includes a post under a body (incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government).

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government concerned in respect of any posts under its control, or the Central Government in respect of any posts under its control, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, where equation is not possible, appoint any member of the Service to any such post without making a declaration that the said post is equivalent in status and responsibility of a post specified in Schedule II.

(5) A member of the Service on appointment to a post referred to in sub-rule (4), in respect of which no pay or scale has been prescribed, shall draw such rate of pay as the State Government, in consultation with the Central Government in the case of a post under the control of the State Government, or as the Central Government in the case of a post under the control of the Central Government may, after taking into account the nature of duties and responsibilities involved in the post, determine.

(6) A member of the Service on appointment to a post referred to in sub-rule (4), in respect of which any pay or scale of pay has been prescribed, shall draw where the pay has been prescribed, the prescribed pay and where scale of pay has been prescribed, such rate of pay not exceeding the maximum of the scale as may be fixed in this behalf by the State Government, or as the case may be, by the Central Government:

Provided that the pay allowed to an officer under this sub-rule and sub-rule (5) shall not at any time be less than what he would have drawn had he not been appointed to a post referred to in sub-rule (4).

(7) At no time the number of members of the Service appointed to hold posts, other than cadre posts referred to in sub-rule (1) and sub-rule (4), which carry pay of Rs. 26000 per mensem and which are reckoned against the State Deputation Reserve, shall except with the prior approval of the Central Government, exceed the number of cadre posts at that level of pay in a State cadre or, as the case may be, in a joint cadre.

**10. Pay of members of the Service appointed to hold more than one post.** The grant of additional pay to a member of the Service appointed to hold more than one post simultaneously shall be regulated :-

(a) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of the Union, by the rules, regulations and orders applicable to officers of the Central Services, Group 'A'.



- (b) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of a State, by the rules, regulations and orders applicable to officers of State Civil Services, Class I.

**11. Authority to exercise powers under rules 6, 7 and 9 in relation to a Joint Cadre.** (1) The powers under rules 6 and 7, in the case of a member of the Service borne on a Joint Cadre, shall be exercised by the Joint Cadre Authority.

(2) The powers under rule 9 in relation to the members of Service and in relation to posts, borne on a Joint Cadre shall be exercised by the Government of the Constituent State concerned.

#### SCHEDULE I

**Principles of pay fixation in cases falling under sub-rules (3) and (4) of rule 4**

In this Schedule, the term—

- (i) 'actual pay' means the pay to which a member of the State Civil Service/Non-State Civil Service, as the case may be, is entitled by virtue of his substantive position in the cadre of that Service or by virtue of his having continuously worked in a temporary or officiating capacity in a higher post for a period of three years or more after following the prescribed procedure, provided the State Government have not revised the scales of pay applicable to the State Civil Service or Non-State Civil Service, as the case may be, after the 1st day of January, 1996. If the pay scales have been revised subsequent to the 1st day of January, 1996, the dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the 1st day of January, 1996 and merged in the revised pay scales, shall be excluded.
- (ii) 'assumed pay' means the pay which a member of the State Civil Service or Non-State Civil Service, as the case may be, would have drawn in a scale of his Service in which he was confirmed or in which had continuously worked in a temporary or officiating capacity for a period of three years or more after following the prescribed procedure, provided the State Government have not revised scales of pay applicable to the State Civil Service or Non-State Civil Service, as the case may be, after the first day of January, 1996. If the pay scales have been revised subsequent to the 1st day of January, 1996, the dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the 1st day of January, 1996 and merged in the revised pay scales, shall be excluded.

(1) Notwithstanding anything contained in the first proviso to sub-rule (1) of rule 3, and the Notes thereunder, the initial pay of a promoted officer or an officer appointed

by selection, as the case may be, shall be fixed at the stage of the senior scale next above his actual pay:

Provided that if such stage of pay happens to be common to different components of the Senior Scale, pay shall be fixed in the lower or the lowest component, as the case may be, of the Senior Scale.

(2) In the case of a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, appointed to the Indian Administrative Service on probation, on any enhancement of his actual pay or assumed pay either as a result of a pay revision or on becoming eligible for an increment or in the event of confirmation in the higher scale of the State Civil Service or the non-State Civil Service, as the case may be, during the period of probation, unless the probation is extended within the meaning of sub-rule (3) of rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, he shall be entitled to have his pay recalculated in accordance with the principles laid down in this Schedule on the basis of his enhanced pay in the State Civil Service or the non-State Civil Service, as the case may be, as if he was promoted to the Indian Administrative Service with effect from the date of such enhancement.

(3) If a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, appointed to the Indian Administrative Service on probation is confirmed with effect from a date prior to the date of his promotion to the Indian Administrative Service in the higher scale of the State Civil Service or the non-State Civil Service, as the case may be, during the period of probation, unless the probation is extended within the meaning of sub-rule (3) of rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, and there is, thus an enhancement of his actual pay or assumed pay, his pay shall be recalculated in accordance with the principles laid down in this Schedule on the basis of his enhanced pay in the Indian Administrative Service with effect from the date of such enhancement.

(4) Where a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, who on the date of his appointment to the Indian Administrative Service had held or is holding continuously a post other than a cadre post under the State Government or the Central Government or on foreign Service and the post is—

(a) in a time scale identical to the time scale of a cadre post; or

(b) equal in status and responsibilities to a cadre post,

and the State Government concerned furnishes a certificate to the Central Government within three months of his appointment to a post other than a cadre post or within three months of the date on which the next junior Select List Officer is appointed to a cadre post, whichever is later, that he would have so officiated in a cadre post under rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, but for his appointment to a post other than a cadre post

as relating to a post under clause (a) for a period not exceeding one year and, with the approval of the Central Government, for a further period not exceeding two years; or as relating to a post in clause (b), for a period not exceeding three years, his initial pay in the Senior Time Scale fixed in accordance with clause (1) shall not be at a stage lower than the pay he drew or draws in the said non-cadre post :

Provided that the number of officers in respect of whom the certificate shall be current at one time shall not exceed one-half of the maximum size of the Select List permissible under sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and follow the order in which the names of such officers appear in the Select List :

Provided further that such certificate shall be given only if, for every senior officer in the Select List appointed to a non-cadre post in respect of which the certificate is given, there is one junior Select List Officer officiating in a senior post under rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :

Provided also that the number of officers in respect of whom the certificate is given, shall not exceed the number of posts by which the number of cadre officers holding non-cadre posts under the control of the State Government falls short of the deputation reserve sanctioned under the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.

(5) The pay of a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, shall not, in any case, be fixed below the minimum of the Senior Time Scale.

(6) If cadre officiation of a promoted officer or of an officer appointed by selection, as the case may be, is followed by appointment in the Service, pay fixed during his officiation shall be taken into account while fixing pay at the time of such appointment.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the pay of a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, shall not at any time exceed the basic pay which he would have drawn as a direct-recruit on that date if he had been appointed to the Indian Administrative Service on the date on which he was appointed to the State Civil Service or in a gazetted post in the non-State Civil Service, after attaining the age of twenty five years, as the case may be.

The fixation of pay of the State Civil Service officers and the non-State Civil Service officers on their appointment or appointed to officiate in cadre posts of the Indian Administrative Service shall be in Proforma A and B.

#### Proforma-A

#### PROFORMA REGARDING FIXATION OF PAY OF STATE CIVIL SERVICE OFFICERS APPOINTED TO OFFICIATE IN INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE CADRE POSTS OR APPOINTED TO INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE

1. Name of the officer :
2. Date of appointment to Indian Administrative Service/appointment to officiate in a Cadre post :
3. Designation of the post held immediately prior to such appointment in Indian Administrative Service :
4. Pay scale and pay drawn in the State Civil Service on the date of appointment to Indian Administrative Service or to officiate in a cadre post.
5. Was the officer substantive or officiating in the post mentioned in serial number 3 :
6. If officiating, for less than three years, what was the substantive post :
7. Pay and pay scale of the substantive post or of the post in which he was officiating for a period of three years or more, continuously and after following the prescribed procedure :
8. Details of all the posts held by the officer before his appointment in the Service, pay scales and pay drawn in these posts :
9. Were the pay scales referred to in serial number 4 and 7 in force from 1-1-1996 :
10. If so, what was the Dearness Allowance admissible with reference to
  - (a) Substantive post :
  - (b) Officiating post :
 (at the rate of Dearness Allowance in force on 1-1-1996 and not with reference to the Dearness Allowance rates in force on the date of appointment to Indian Administrative Service/appointment to officiate in Indian Administrative Service).
11. If the answer to serial number 9 is 'NO', when was the pay scale revised for the first time after 1-1-1996 and what were the pre-revised scale for the post referred to in serial number 7.
12. What was the quantum of Dearness Allowance/ Dearness Pay/Interim relief sanctioned after 1-1-1996 and merged in the scale for the post referred to in serial number 7.
13. Number of completed years of service in Class I or Group 'A' of State Civil Service.
14. Proposal of the State Government for fixation of pay and basis thereof.

#### Proforma 'B'

#### PROFORMA FOR FIXATION OF PAY OF NON-STATE CIVIL SERVICE OFFICERS APPOINTED TO INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE

1. Name of officer :

2. Date of appointment to the Service :
3. Designation of the post held immediately prior to appointment to Service :
4. Pay and pay scale of the post referred to in serial number 3 :
5. Whether the pay was substantive or officiating :
6. If officiating for less than 3 year, what was the substantive pay :
7. Designation and the pay scale of the post in which the officer was substantive :
8. Details of the all the posts held by the officer before his appointment in the Service, pay scale and pay drawn in these posts :
9. State whether the pay scales of the substantive post and the post in which the officer was officiating for three years or more were in force from 1-1-1996 :
10. If the answer to serial number 9 above is yes, what is the Dearness Allowance admissible to the officer at the rates in force on 1-1-1996 in his—
  - (a) Substantive post :
  - (b) Officiating post :
11. If the answer to serial number 9 is "no" what were the pre-revised pay scales of the posts in which the officer was —
  - (a) Substantive :
  - (b) Officiating :
12. What is the quantum of Dearness Allowance merged in the revised pay scales of —
  - (a) Substantive post :
  - (b) Officiating post :
13. No. of completed years service in a gazetted post in the non-State Civil Service after attaining the age of twenty-five years :
14. Proposal of State Government for fixation of pay and basis therefor :

**A—Posts carrying pay above the Senior Scale in the Indian Administrative Service under State Governments.**

## SCHEDULE II

### A. ANDHRA PRADESH

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Director General Dr. Marri Chenna Reddy, Human Resource Development, Institute of Andhra Pradesh	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Chief Commissioner of Land Administration	Rs. 26,000/- (Fixed)
(4) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(5) Chief Electoral Officer and Ex-Officio Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 22400-525-24500
(7) Commissioners	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner and Director of Sugar	Rs. 18400-500-22400
(9) Commissioner for Panchayat Raj	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner, Handlooms	Rs. 18400-500-22400
(11) Commissioner of Industries	Rs. 18400-500-22400
(12) Commissioner of Rural Development	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner, Employment and Training	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner, Women Development and Child Welfare	Rs. 18400-500-22400
(15) Commissioner, Tribal Welfare	Rs. 18400-500-22400
(16) Commissioner, Sericulture	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner of Transport	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner of Endowments	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(20) Commissioner of Labour	Rs. 18400-500-22400
(21) Commissioner of Departmental Inquiries	Rs. 18400-500-22400
(22) Commissioner-cum-Director, Municipal Administration	Rs. 18400-500-22400
(23) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(24) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400

(25) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(26) Commissioner, Relief and Ex-Officio Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(27) Resident Commissioner, Andhra Pradesh Bhawan, New Delhi	Rs. 18400-500-22400

**ARUNACHAL PRADESH-GOA-MIZORAM-UNION TERRITORIES****Post under the Government of Arunachal Pradesh**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Principal Secretary-cum-Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(3) Commissioner-cum-Secretary (PWD/RWD)	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner-cum-Secretary (Finance)	Rs. 18400-500-22400
(5) Divisional Commissioner (East)	Rs. 18400-500-22400
(6) Divisional Commissioner (West)	Rs. 18400-500-22400
(7) Commissioner-cum-Secretary (Home)	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner-cum-Secretary (Education)	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Government of Goa**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Principal Secretary	Rs. 22400-525-24500
(3) Commissioner-cum-Secretary (Finance)	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner-cum-Secretary (Education and Health)	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Government of Mizoram**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Commissioner or Secretary (Development)	Rs. 18400-500-22400
(3) Commissioner or Secretary (Finance)	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner or Secretary (Revenue)	Rs. 18400-500-22400
(5) Commissioner or Secretary (Home)	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Andaman and Nicobar Islands**

(1) Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(2) Commissioner-cum-Secretary (Development)	Rs. 18400-500-22400
(3) Commissioner-cum-Secretary (Finance)	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner-cum-Secretary (Shipping and Transport)	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Union Territory of Chandigarh**

(1) Advisor to the Administrator, Chandigarh	Rs. 22400-525-24500
(2) Secretary (Home)	Rs. 18400-500-22400
(3) Secretary (Finance)	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Union Territory of Daman and Diu/Dadra and Nagar Haveli**

(1) Development Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(2) Finance Secretary	Rs. 18400-500-22400

**Post under the Government of National Capital Territory of Delhi**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Principal Secretary (Home)	Rs. 22400-525-24500
(3) Principal Secretary (Finance)	Rs. 22400-525-24500
(4) Principal Secretary (UD)	Rs. 22400-525-24500
(5) Principal Secretary (Health and F.W.)	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner and Secretary (Development)	Rs. 18400-500-22400
(7) Commissioner and Secretary (PWD/LandB/LSG)	Rs. 18400-500-22400

(8) Commissioner and Secretary (Industries)	Rs. 18400-500-22400
(9) Commissioner/Secretary (Food and Supply)	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner/Secretary (Planning and Infrastructure)	Rs. 18400-500-22400
(11) Secretary (Tourism, Culture, Archaeology and Academies)	Rs. 18400-500-22400
(12) Secretary (Water and Power)	Rs. 18400-500-22400
(13) Secretary (Environment and Forest and Non-Conventional Energy)	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner (Sales Tax)	Rs. 18400-500-22400
(15) Director, Vigilance	Rs. 18400-500-22400
(16) Member, Appellate Tribunal Sales Tax	Rs. 18400-500-22400
(17) Director of Education	Rs. 18400-500-22400
(18) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner (Appeals)	Rs. 18400-500-22400
(20) Secretary to Lt. Governor	Rs. 18400-500-22400
(21) Commissioner and Secretary (Education)	Rs. 18400-500-22400
(22) Commissioner and Secretary (Transport)	Rs. 18400-500-22400

**POST UNDER THE GOVERNMENT OF PONDICHERRY**

(1) Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(2) Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(3) Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	Rs. 18400-500-22400

**ASSAM-MEGHALAYA****ASSAM**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Chairman, Assam Administrative Tribunal	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Addl. Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(5) Commissioner of Division	Rs. 18400-500-22400
(6) Commissioner for Agricultural Production and Rural Development and Special Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(7) Chairman, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner and Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(9) Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(10) Chief Electoral Officer and ex-officio Commissioner and Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400

**MEGHALAYA**

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government/Development Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(3) Commissioner of Division	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner and Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400

**BIHAR**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Member, Board of Revenue	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Development Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(4) Agricultural Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(5) Commissioner and Secretary (Finance)	Rs. 22400-525-24500

(6) Commissioner and Secretary (Home)	Rs. 22400-525-24500
(7) Vigilance Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(8) Commissioner and Secretary, Water Resources, Rural Development, Revenue and Land Reforms and Industries	Rs. 22400-525-24500
(9) Commissioner and Secretary, Personnel Department	Rs. 22400-525-24500
(10) Commissioner and Secretary, Health Department	Rs. 22400-525-24500
(11) Commissioner and Secretary, Education Department	Rs. 22400-525-24500
(12) Relief and Rehabilitation Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(13) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(15) Chairman, Bihar State Staff Selection Commission	Rs. 18400-500-22400
(16) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(17) Chief Electoral Officer-cum-Secretary	Rs. 18400-500-22400
(18) Secretary, PWD Department	Rs. 18400-500-22400
(19) Secretary, Welfare	Rs. 18400-500-22400
(20) Secretary, Urban Development	Rs. 18400-500-22400
(21) Secretary, Food, Civil Supplies and Commerce	Rs. 18400-500-22400
(22) Secretary, Energy Department	Rs. 18400-500-22400
(23) Secretary, Cabinet Sectt.	Rs. 18400-500-22400
(24) Secretary, Forest and Environment	Rs. 18400-500-22400
(25) Secretary, Labour, Employment and Training	Rs. 18400-500-22400
(26) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(27) Secretary, Science and Technology Department	Rs. 18400-500-22400
(28) Secretary, Animal Husbandry and Fisheries Department	Rs. 18400-500-22400
(29) Secretary, Cooperative Department	Rs. 18400-500-22400
(30) Secretary, Building Construction Department	Rs. 18400-500-22400
(31) Secretary, Public Health Engineering Department	Rs. 18400-500-22400
(32) Secretary, Minor Irrigation Department	Rs. 18400-500-22400
(33) Secretary, Information and Public Relation Department	Rs. 18400-500-22400
(34) Secretary, Transport Department	Rs. 18400-500-22400
(35) Secretary, Institutional Finance and Programme Implementation Department	Rs. 18400-500-22400
(36) Secretary, Panchayati Raj and Rural Engineering Department	Rs. 18400-500-22400
(37) Inspector General Registration-cum-Secretary	Rs. 18400-500-22400
(38) Departmental Enquiry Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(39) Secretary to Lokayukta	Rs. 18400-500-22400
(40) Secretary, Excise and Prohibition Department	Rs. 18400-500-22400

**CHHATTISGARH**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) President, Board of Revenue	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Secretary to the Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Agriculture Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(5) Chief Electoral Officer	Rs. 18400-500-22400
(6) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(7) Member, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400

(9) Commissioner, Government of Chhattisgarh, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(10) Registrar, Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(11) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(12) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(13) Director, Academy of Administration	Rs. 18400-500-22400
(14) Labour Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(15) Excise Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(16) Commissioner, Tribal Development	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner, Industries	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner, Treasuries, Small Savings and Lotteries	Rs. 18400-500-22400

**GUJARAT**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Commissioner of Training and Director, Sardar Patel Institute of Public Administration	Rs. 22400-525-24500
(5) Principal Secretary to Governor	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner of Sales Tax	Rs. 22400-525-24500
(7) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(8) Development Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(9) Industries Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner of Departmental Enquiries	Rs. 18400-500-22400
(11) Settlement Commissioner and Director of Land Records	Rs. 18400-500-22400
(12) Commissioner of Land Reforms	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner of Cottage and Rural Industries	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner of Transport	Rs. 18400-500-22400
(15) Commissioner of Higher Education	Rs. 18400-500-22400
(16) Member, Urban Land Tribunal	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner of Fisheries	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner of Health, Medical Services and Medical Education	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner of Women and Child Development	Rs. 18400-500-22400
(20) Commissioner of Geology and Mining	Rs. 18400-500-22400
(21) Commissioner of Rural Development	Rs. 18400-500-22400
(22) Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400

**HARYANA**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Financial Commissioner/Principal Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Financial Commissioner/Principal Secretary/Member, Sales Tax Tribunal	Rs. 22400-525-24500
(4) Commissioner of Divisions	Rs. 18400-500-22400
(5) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(6) Transport Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(7) Prohibition, Excise and Taxation Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(8) Resident Commissioner, Haryana Bhavan, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(9) Registrar, Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(10) Director, Agriculture	Rs. 18400-500-22400
(11) Chief Electoral Officer	Rs. 18400-500-22400

(12) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(13) Director, Industries	Rs. 18400-500-22400
(14) Director, Town and Country Planning-cum-Urban Estate and Colonisation	Rs. 18400-500-22400
(15) Director, Higher Education	Rs. 18400-500-22400
(16) State Transport Controller	Rs. 18400-500-22400

**HIMACHAL PRADESH**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Financial Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(3) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(4) Commissioner-cum-Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(5) Commissioner-cum-Secretary (Lok Ayukta)	Rs. 18400-500-22400
(6) Chief Election Officer-cum-Secretary (Election)	Rs. 18400-500-22400
(7) Director, Industries	Rs. 18400-500-22400
(8) Excise and Taxation Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(9) Director, Social and Women's Welfare	Rs. 18400-500-22400
(10) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400

**JAMMU AND KASHMIR**

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(3) Financial Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(4) Chairman, Jammu and Kashmir Special Tribunal	Rs. 22400-525-24500
(5) Commissioner and Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(6) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(7) Resident Commissioner	Rs. 18400-500-22400

**JHARKHAND**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Development Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Commissioner and Secretary/Principal Secretary	Rs. 22400-525-24500
(4) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(5) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(6) Chief Electoral Officer	Rs. 18400-500-22400
(7) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(8) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400

**KARNATAKA**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Additional Chief Secretary to the Government-cum-Development Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(4) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(5) Chairman, Karnataka Appellate Tribunal	Rs. 22400-525-24500
(6) Chief Electoral Officer and ex-officio Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(7) Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 22400-525-24500
(8) Resident Commissioner, Karnataka Bhawan	Rs. 22400-525-24500
(9) Director General of Administrative Reforms and Training, Administrative Training Institute, Mysore	Rs. 22400-525-24500
(10) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400



(11) Commissioner for Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(12) Inspector General of Registration and Commissioner of Stamps	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner for Excise	Rs. 18400-500-22400
(14) Director of Industries and Commerce and Commissioner for Industrial Development	Rs. 18400-500-22400
(15) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(16) Registrar, Cooperative Societies and Director of Cooperative Audit	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner for Food and Civil Supplies	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner for Transport and Road Safety	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner for Cane Development and Director of Sugar	Rs. 18400-500-22400
(20) Commissioner, Public Instructions	Rs. 18400-500-22400
(21) Commissioner for Sericulture Development and Director of Sericulture	Rs. 18400-500-22400
(22) Commissioner for Collegiate Education	Rs. 18400-500-22400
(23) Commissioner for Agriculture	Rs. 18400-500-22400
(24) Commissioner for Health and Family Welfare Services	Rs. 18400-500-22400
(25) Commissioner Watershed Development Department and E/O Secretary to Government Agriculture and Horticulture Department	Rs. 18400-500-22400
(26) Secretary, Malnad Area Development Board	Rs. 18400-500-22400
(27) Executive Director, Karnataka Jalasamwardhana Sangha	Rs. 18400-500-22400
(28) Commissioner for Labour	Rs. 18400-500-22400
(29) Commissioner of Backward Classes	Rs. 18400-500-22400
(30) Commissioner for Public Instructions, Hubli	Rs. 18400-500-22400
(31) Commissioner for Public Instructions, Gulbarga	Rs. 18400-500-22400
(32) Commissioner of Social Welfare	Rs. 18400-500-22400
(33) Commissioner of Tourism	Rs. 18400-500-22400
(34) Commissioner of Employment and Training	Rs. 18400-500-22400
(35) Commissioner for Information and E/O Secretary, ITYS	Rs. 18400-500-22400
(36) Member, Karnataka Appellate Tribunal	Rs. 18400-500-22400
(37) Commissioner, Survey, Settlement and Land Records	Rs. 18400-500-22400

**KERALA**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Agriculture Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(5) Commissioners	Rs. 18400-500-22400
(6) Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(7) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(8) Director of Agriculture	Rs. 18400-500-22400
(9) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(10) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(11) Director of Industries and Commerce	Rs. 18400-500-22400
(12) Registrar of Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400

**MADHYA PRADESH**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary/President, Board of Revenue	Rs. 26,000 (Fixed)

(3) Additional Chief Secretary/Director General of Academy of Administration of Madhya Pradesh	Rs. 26,000 (Fixed)
(4) Principal Secretary	Rs. 22400-525-24500
(5) Agriculture Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(6) Development Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(7) Administrative Member, Board of Revenue	Rs. 22400-525-24500
(8) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(9) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(10) Member, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(11) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(12) Land Records and Settlement Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner, Madhya Pradesh, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(14) Registrar, Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(15) Secretary to the Governor, Madhya Pradesh	Rs. 18400-500-22400
(16) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(17) Director, Academy of Administration	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner, Industries	Rs. 18400-500-22400
(19) Labour Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(20) Secretary, Lokayukt, Madhya Pradesh	Rs. 18400-500-22400
(21) Inspector General of Registration and Suptd. of Stamps	Rs. 18400-500-22400
(22) Excise Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(23) Commissioner, Tribal Development	Rs. 18400-500-22400
(24) Commissioner, Scheduled Caste Welfare	Rs. 18400-500-22400
(25) Commissioner, Backward Class Welfare	Rs. 18400-500-22400
(26) Commissioner, Women and Child Development	Rs. 18400-500-22400
(27) Commissioner, Public Instruction	Rs. 18400-500-22400
(28) Commissioner, Higher Education	Rs. 18400-500-22400
(29) Chief Electoral Officer	Rs. 18400-500-22400
(30) Commissioner, Health Services	Rs. 18400-500-22400

**MAHARASHTRA**

(1) Chief Secretary to the Government and Development Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Additional Chief Secretary to the Government, Vidharba Development	Rs. 26,000
(4) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(5) Commissioner of Department Enquiries	Rs. 22400-525-24500
(6) Director General, Yeshwantrao Chavan Academy of Development and Administration	Rs. 22400-525-24500
(7) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner of Division	Rs. 18400-500-22400
(9) Commissioner of Sales Tax	Rs. 18400-500-22400
(10) Settlement Commissioner and Director of Land Records	Rs. 18400-500-22400
(11) Commissioner for Cooperation and Registrar of Coop. Societies	Rs. 18400-500-22400
(12) Commissioner for Cooperation and Registrar	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner Food and Drug Administration	Rs. 18400-500-22400
(14) Chief Protocol Officer and Secy. to Government	Rs. 18400-500-22400
(15) Commissioner of Employees State Insurance Scheme	Rs. 18400-500-22400
(16) Chief Electoral Officer and Secy. to Government	Rs. 18400-500-22400

(17) Development Commissioner Industries	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner of Prohibition and Excise	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner of Sugar	Rs. 18400-500-22400
(20) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(21) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(22) Special Commissioner, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(23) Transport Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(24) Dairy Development Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(25) Commissioner of Agriculture	Rs. 18400-500-22400
(26) Commissioner of Tribal Development	Rs. 18400-500-22400

**MANIPUR-TRIPURA****MANIPUR**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (fixed) (After 30 years service)
(2) Additional Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(3) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(5) Director General of State Academy of Training	Rs. 18400-500-22400
(6) Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(7) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(8) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400

**TRIPURA**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (fixed) (After 30 years service)
(2) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(3) Commissioner-cum-Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(4) Resident Commissioner, Tripura Bhavan, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(5) Special Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(6) Chief Executive Officer, Tripura Tribal Area Autonomous Distt. Council	Rs. 18400-500-22400

**NAGALAND**

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary and Home Commissioner to be redesignated as Additional Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(3) Additional Chief Secretary, Planning and Coordination to be redesignated as Additional Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(4) Principal Secretary	Rs. 22400-525-24500
(5) Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner and Secretary to Government to be redesignated as Commissioner and Secretary	Rs. 18400-500-22400
(7) Divisional Commissioner to be redesignated as Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(8) Director Administrative Training Institute	Rs. 18400-500-22400
(9) Special Secretary to Governor to be redesignated as Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner Taxes and Excise	Rs. 18400-500-22400
(11) Resident Commissioner	Rs. 18400-500-22400

**ORISSA**

(1) Chief Secretary to the Government and Chief Development Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Member, Board of Revenue	Rs. 26000 (Fixed)
(3) Chief Administrator (Special Area Development) and ex-officio Member, Board of Revenue and Special Chief Secretary to Government)	Rs. 26000 (Fixed)
(4) Additional Chief Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(5) Special Relief Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(6) Agriculture Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(7) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(8) Chief Electoral Officer	Rs. 22400-525-24500
(9) Additional Development Commissioner and Secretary to Government Planning and Coordination	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner, Tribal and Harijan Welfare	Rs. 22400-525-24500
(11) Director General, Training Coordination, Gopabandhu Academy of Administration, Bhubaneswar	Rs. 22400-525-24500
(12) Revenue Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner, Land and Reforms	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(15) Commissioner, Land Reforms and Settlement	Rs. 18400-500-22400
(16) Transport Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner, Consolidation	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner-cum-Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner-cum-Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(20) Commissioner-cum-Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(21) Special Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400

**PUNJAB**

(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Financial Commissioner (Development)	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Financial Commissioner/Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Financial Commissioner (Appeals)	Rs. 22400-525-24500
(5) Chief Electoral Officer and Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner of Divisions	Rs. 18400-500-22400
(7) Excise and Taxation Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(8) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(9) Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(10) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(11) Director/Executive Director, Punjab State Institute of Public Admn.	Rs. 18400-500-22400
(12) Registrar Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(13) Director, Food and Civil Supplies	Rs. 18400-500-22400
(14) Director Institutional Finance and Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(15) Resident Commissioner, Government of Punjab, New Delhi	Rs. 18400-500-22400

**RAJASTHAN**

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Chairman Board of Revenue	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Chairman, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal	Rs. 26,000 (Fixed)

(4) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(5) Chairman, Rajasthan Tax Board	Rs. 22400-525-24500
(6) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(7) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(8) Commissioner for Departmental Enquiries	Rs. 18400-500-22400
(9) Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(10) Commissioner, Command Area Development	Rs. 18400-500-22400
(11) Transport Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(12) Member, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(13) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(14) Member, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(15) Registrar, Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(16) Excise Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner, Labour and Employment	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner, Industries	Rs. 18400-500-22400
(19) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(20) Chief Electoral Officer and Ex-Officio Principal Secretary to Government, Elections	Rs. 18400-500-22400

**SIKKIM**

(1) Chief Secretary to Government	Rs. 26000 (Fixed)
(2) Additional Chief Secretary	Rs. 22400-525-24500
(3) Principal Secretary	Rs. 22400-525-24500
(4) Commissioner-cum-Secretary	Rs. 18400-500-22400

**TAMILNADU**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Vigilance Commissioner	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Commissioner, Revenue Admn.	Rs. 26,000 (Fixed)
(4) Special Commissioners	Rs. 22400-525-24500
(5) Chief Electoral Officer and Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(6) Commissioner of Prohibition, Excise and Narcotics	Rs. 22400-525-24500
(7) Commissioner of Agricultural Income Tax	Rs. 22400-525-24500
(8) Secretary, State Planning Commission	Rs. 22400-525-24500
(9) Commissioner of Transport	Rs. 22400-525-24500
(10) Commissioner for Disciplinary Proceedings, Madras	Rs. 18400-500-22400
(11) Resident Commissioner, Tamil Nadu House, New Delhi	Rs. 18400-500-22400
(12) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(13) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(14) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(15) Industries Commissioner and Director of Industries and Commerce	Rs. 18400-500-22400
(16) Director of Sugar	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner for Civil Supplies	Rs. 18400-500-22400
(18) Director of Town Panchayats	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner for Milk Production	Rs. 18400-500-22400
(20) Registrar of Cooperative Societies	Rs. 18400-500-22400
(21) Commissioner for Labour	Rs. 18400-500-22400
(22) Commissioner of Municipal Administration	Rs. 18400-500-22400

(23) Commissioner of Rural Development	Rs. 18400-500-22400
<b>UTTARANCHAL</b>	
(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Director General Uttaranchal Administrative Academy, Nainital	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(4) Chief Revenue Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(5) Principal Secretary and Forest and Rural Development Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(6) Principal Secretary and Infrastructure Development Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(7) Principal Secretary and Social Welfare Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(8) Resident Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(9) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(10) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(11) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(12) Divisional Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(13) Commissioner, Excise	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner, Taxes	Rs. 18400-500-22400
(15) Chief Executive Officer, Tourism Board	Rs. 18400-500-22400
<b>UTTAR PRADESH</b>	
(1) Chief Secretary	Rs. 26,000 (Fixed)
(2) Chairman, Board of Revenue and Adviser Land Reforms	Rs. 26,000 (Fixed)
(3) Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	Rs. 26,000 (Fixed)
(4) Member, Revenue Board	Rs. 26,000 (Fixed)
(5) Director General, Training	Rs. 26,000 (Fixed)
(6) Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut, Lucknow, Allahabad, Kanpur)	Rs. 22400-525-24500
(7) Principal Secretary to Government	Rs. 22400-525-24500
(8) Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 22400-525-24500
(9) Agriculture Production Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(10) Industrial Development Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(11) Social Welfare Commissioner	Rs. 22400-525-24500
(12) Principal Secretary to Governor	Rs. 22400-525-24500
(13) Principal Secretary to Chief Minister	Rs. 22400-525-24500
(14) Director General, State Institute of Rural Development	Rs. 22400-525-24500
(15) Divisional Commissioners	Rs. 18400-500-22400
(16) Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(17) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(18) Sales Tax Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner of Rural Development	Rs. 18400-500-22400
(20) Transport Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(21) Registrar Co-operative Societies	Rs. 18400-500-22400
(22) Director, Administrative Training Institute	Rs. 18400-500-22400
(23) Director of Industries	Rs. 18400-500-22400
(24) Excise Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(25) Director, Handlooms	Rs. 18400-500-22400
(26) Cane Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(27) Secretary, Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400

(28) Director General of Prison	Rs. 18400-500-22400
(29) Director General, Tourism	Rs. 18400-500-22400
(30) Labour Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(31) Chairman, Admn. Tribunal. II	Rs. 18400-500-22400
(32) Member (Judicial) Board of Revenue	Rs. 18400-500-22400
(33) Commissioner, Food	Rs. 18400-500-22400
(34) Entertainment Tax Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(35) Inspector General of Registration and Stamps	Rs. 18400-500-22400
(36) Commissioner for Consolidation	Rs. 18400-500-22400
(37) Principal Staff Officer to Chief Secretary	Rs. 18400-500-22400
(38) Director, Culture	Rs. 18400-500-22400

**WEST BENGAL**

(1) Chief Secretary to the Government	Rs. 26000 (Fixed)
(2) Commissioner General, Land Reforms	Rs. 26000 (Fixed)
(3) Commissioner, Food and ex-officio Secretary, Food and Supplies Department	Rs. 26000 (Fixed)
(4) Principal Secretary, Forests	Rs. 26000 (Fixed)
(5) Principal Secretary to the Government (Home, Finance, Higher Education, Social Welfare, Relief, Animal Resources Development, Panchayat and Rural Development Departments)	Rs. 22400-525-24500
(6) Principal Secretary to the Government	Rs. 22400-525-24500
(7) Commissioner of Division	Rs. 18400-500-22400
(8) Secretary/Special Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400
(9) Land Reforms Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(10) Director, Administrative Training Institute	Rs. 18400-500-22400
(11) Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400
(12) Secretary to Chief Minister	Rs. 18400-500-22400
(13) Director, Social Welfare	Rs. 18400-500-22400
(14) Commissioner for Commercial Taxes	Rs. 18400-500-22400
(15) Labour Commissioner	Rs. 18400-500-22400
(16) Commissioner of Backward Classes Welfare	Rs. 18400-500-22400
(17) Commissioner of Panchayats	Rs. 18400-500-22400
(18) Commissioner of Family Welfare	Rs. 18400-500-22400
(19) Commissioner of School Education	Rs. 18400-500-22400
(20) Commissioner of Excise	Rs. 18400-500-22400

B-Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay. (1) The number of posts in the Selection Grade in a State Cadre shall be equal to 20 per cent of total number of senior posts in the State reduced by the number of posts carrying pay above the senior scale in the State subject to a minimum of 15 per cent of the senior posts in the State:

**Explanation I** - The expression "senior posts in the State" shall mean senior posts under a State Government as specified in item 1 of the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955.

**Explanation II** - The number of Selection Grade posts shall be worked out under this clause on the basis of the authorized strength and no changes need be made consequent on a temporary addition to a cadre/temporary holding in abeyance of a cadre post.

(2) The State Government concerned shall be competent to grant a special allowance for any of the posts specified in this part of the Schedule either individually or with reference to a group or class of such posts.

(3) The amount of any special allowance which may be sanctioned by the State Government under clause (2) shall be Rs. 400 for posts in the Junior Time Scale, Rs. 600/- for posts in the Senior Time Scale, Rs. 800/- for posts in the

Junior Administrative Grade and Rs.1000/- for posts in the Selection Grade.

(4) Post in the junior time scale of the Service have not

#### S. No. ANDHRA PRADESH

- (1) Addl./Joint /Deputy Secretaries to Government
- (2) Secretary to Chief Commissioner, Land Administration
- (3) Addl./Joint Secretary to Chief Commissioner, Land Administration
- (4) Collectors and District Magistrates
- (5) Special Collectors
- (6) Special Officer and Competent Authority, Urban Land Ceilings
- (7) Secretary to Chief Commissioner, Land Administration
- (8) Joint Collector
- (9) Joint Commissioner of Excise (Enforcement)
- (10) Deputy Commissioner (Excise)
- (11) Secretary to Commissioner (Excise)
- (12) Director of Civil Supplies
- (13) Director, Tourism
- (14) Secretary, Andhra Pradesh Public Service Commission
- (15) Project Officer, Integrated Tribal Development Agency/Project Director, District Rural Development Agency, Chief Executive Officer, Zilla Parishad
- (16) Director of Settlement, Survey and Land Records
- (17) Director of Social Welfare
- (18) Joint Commissioner (Commercial Taxes)
- (19) Deputy Commissioner (Commercial Taxes)
- (20) Secretary to Commissioner (Commercial Taxes)
- (21) Chief Rationing Officer
- (22) Director of Distilleries and Addl. Secretary to Commissioner of Excise

#### ARUNACHAL PRADESH-GOA-MIZORAM- UNION TERRITORIES

##### ARUNACHAL PRADESH

- (1) Secretary (Industries)
- (2) Secretary (Supply and Transport)
- (3) Secretary (General Administration)
- (4) Joint Secretary (Political)
- (5) Joint Secretary (Planning and Development)
- (6) Secretary to Chief Minister
- (7) Secretary to Governor
- (8) Registrar, Co-operative Societies
- (9) Director of Supply and Transport
- (10) Secretary to Civil Supplies
- (11) Deputy Commissioner (Districts)

##### GOA

- (1) Secretary to Governor
- (2) Secretary to Chief Minister
- (3) Secretary to Government

been specified in the Schedule but it shall be within the competence of the State Governments concerned to sanction any special allowance to be attached to such posts.

(4) Commissioner (Sales Tax)

(5) Director of Industries and Mines

(6) Collector/District Magistrate

(7) Commissioner of Excise

#### MIZORAM

- (1) Secretary to Governor
- (2) Secretary to Chief Minister
- (3) Registrar, Co-operative Societies
- (4) Director of Supply and Transport
- (5) Director of Industries
- (6) Deputy Commissioners (Districts)
- (7) Secretaries
- (8) Joint Secretary (Finance)
- (9) Joint Secretary (Pol. and Vig.)

#### ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS

- (1) Secretary to Lt. Governor
- (2) Deputy Commissioner (Districts)
- (3) Deputy Development Commissioner/Special Secretary

#### CHANDIGARH

- (1) Deputy Commissioner (Districts)
- (2) Joint Secretary (Finance)

#### DAMAN and DIU/DADRA and NAGAR HAVELI

- (1) Collector/Distt. Magistrate (Daman, Diu/Dadra and Nagar Haveli)

#### NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

- (1) Dy. Commissioner (Districts)
- (2) Secretary (Services)
- (3) Director of Training (UTCS)
- (4) Director of Social Welfare
- (5) Director of Training and Technical Education
- (6) Registrar, Co-operative Societies
- (7) Labour Commissioner
- (8) Commissioner (Excise and Ent.)
- (9) Addl. Director of Education (Admn.)
- (10) Addl. Commissioner, Sales Tax
- (11) Director, Agricultural Marketing
- (12) Additional Secretary (Education)
- (13) Additional Secretary (Finance)
- (14) Secretary to Chief Minister

#### LAKSHADWEEP

- (1) Collector-cum-Development Commissioner

#### PONDICHERRY

- (1) Secretary to Government
- (2) Resident Commissioner



- (3) Secretary to Lt. Governor

**ASSAM-MEGHALAYA****ASSAM**

- (1) Member, Board of Revenue
- (2) Deputy Commissioner
- (3) Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary/  
Deputy Secretary to Government
- (4) Director, Evaluation and Monitoring
- (5) Secretary to Chief Minister
- (6) Commissioner of Transport
- (7) Secretary to Governor
- (8) Director of Industries
- (9) Registrar of Co-operative Societies
- (10) Director of Land Records
- (11) Commissioner of Excise
- (12) Commissioner of Taxes
- (13) Director of Panchayats and Rural Development
- (14) Director of Training and Principal, Assam  
Administrative Staff College
- (15) State Enquiry Officer for Departmental Proceedings
- (16) Project Director, IRDA/IIDP/Additional Deputy  
Commissioner
- (17) Labour Commissioner

**MEGHALAYA**

- (1) Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary/  
Deputy Secretary to Government
- (2) Special Secretary to Governor
- (3) Commissioner of Excise
- (4) Director of Supply and Trade
- (5) Director, C and RD
- (6) Deputy Commissioner
- (7) Commissioner of Taxes
- (8) Registrar of Co-operative Societies
- (9) District Planning Officer/Additional Deputy  
Commissioner

**BIHAR**

- (1) Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
- (2) District Magistrate and Collector/Addl. D.M.
- (3) Settlement Officer/DDC-cum-CEO District Board
- (4) Registrar, Co-operative Societies
- (5) Secretary, Board of Revenue
- (6) Director, Land Records and Survey
- (7) Inspector General Prisons
- (8) Labour Commissioner
- (9) Director, Panchayati Raj
- (10) Director, Industries
- (11) Director, Training and Employment
- (12) Director, Social Security
- (13) Director, Welfare
- (14) State Transport Commissioner

**CHHATTISGARH**

- (1) Collector

- (2) Executive Director, DRDA and ex-officio, CEO,  
District Panchayat
- (3) Additional Collector
- (4) Additional Secretary/Joint Secretary/Dy. Secretary  
to Government
- (5) Director, Food, Civil Supplies and Consumer  
Protection
- (6) Secretary, Chhattisgarh Public Service Commission
- (7) Director Public Instruction
- (8) Director Women and Child Development
- (9) Director, Land Records
- (10) Director, Urban Administration
- (11) Director, Panchayat and Social Welfare
- (12) Director, Agriculture

**GUJARAT**

- (1) Secretary to Chief Minister
- (2) Additional/Joint/Deputy Secretary to Government
- (3) Collector
- (4) District Development Officer
- (5) Director of Municipalities
- (6) Registrar of Co-operative Societies
- (7) Commissioner of Labour
- (8) Commissioner, Entertainment Tax
- (9) Director of Employment and Training
- (10) Director of Civil Supplies
- (11) Director of Social Welfare
- (12) Director of Food
- (13) Additional Commissioner of Industries
- (14) Additional Development Commissioner
- (15) Additional Commissioner of Sales Tax

**HARYANA**

- (1) Joint/Deputy Secretary to Government
- (2) Labour Commissioner
- (3) Director of Food and Supplies
- (4) Director, Public Relations, Grievances and Cultural  
Affairs
- (5) Director, Hospitality and Tourism
- (6) Director of Consolidation, Land Records and  
Special Collector
- (7) Director, Social Justice and Empowerment and  
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes
- (8) Director, Women and Child Development
- (9) Director of Industries Training
- (10) Director, Primary Education
- (11) Director of Secondary Education
- (12) Director, Environment
- (13) Director, Sports
- (14) Director, Development and Panchayats
- (15) Director, Rural Development and Institutional  
Finance
- (16) Director of Supplies and Disposals
- (17) Director of Local Bodies
- (18) Deputy Commissioner
- (19) Additional Commercial Taxation Commissioner

960 91/07-11

- (21) Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency/Additional Collectors

#### HIMACHAL PRADESH

- (1) Secretary/Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary to Government
- (2) Secretary, Public Service Commission
- (3) Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration
- (4) Registrar of Cooperative Societies
- (5) Director of Civil Supplies
- (6) Director, Panchayati Raj-cum-Director of Rural Integrated Development
- (7) Labour Commissioner and Director of Employment and Training
- (8) Director, Transport
- (9) Director, Tourism
- (10) Director, Vigilance
- (11) Settlement Officer
- (12) Deputy Commissioners
- (13) Commissioner for Departmental Enquiries
- (14) Additional Deputy Commissioner
- (15) Additional Registrar of Cooperative Societies
- (16) Additional Director of Industries
- (17) Director of Land Records
- (18) Director, Public Finance and Public Enterprises
- (19) Director, Urban Local Bodies

#### JAMMU AND KASHMIR

- (1) Joint Financial Commissioner (Agrarian Reforms)
- (2) Sales Tax Commissioner
- (3) Excise Commissioner
- (4) Registrar, Cooperative Societies
- (5) Director of Tourism
- (6) Director of Industries and Commerce
- (7) Deputy Commissioners
- (8) Director of Food and Supplies
- (9) Secretaries/Special Secretaries/Additional Secretaries to Government
- (10) Secretary to Chief Minister
- (11) Secretary to Governor
- (12) Labour Commissioner
- (13) Chief Electoral Officer
- (14) Settlement Commissioner
- (15) Commissioner for Departmental Enquiries
- (16) Additional Deputy Commissioners

#### JHARKHAND

- (1) Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
- (2) Tribal Development Commissioner Director, Industries
- (3) I.G. Prison
- (4) I.G. Registration
- (5) State Transport Commissioner
- (6) Labour Commissioner

- (7) Registrar, Cooperative Societies
- (8) Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner
- (9) Settlement Officer/DDC
- (10) Commissioner, Commercial Taxes
- (11) Director, Panchayati Raj
- (12) Director, Land Acquisition and Land Records

#### KARNATAKA

- (1) Additional/Joint/Deputy Secretary to Government
- (2) Director of Women and Child Development Department
- (3) Secretary, Karnataka Public Service Commission
- (4) Director, Rural Infrastructure and E/O AS/JS/DS to Government, RDPR
- (5) Addl./Joint Director, Food and Civil Supplies
- (6) Joint/Addl. Commissioner of Commercial Taxes
- (7) Director of Agricultural Marketing
- (8) Director SEP and E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government, ADPR
- (9) Director of Pre-University Education
- (10) Director of Municipal Administration
- (11) Director, Information Technology and Biotechnology
- (12) Director, Project Planning and Monitoring Unit and E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government, Rural Development and Panchayat Raj Department
- (13) Addl. Resident Commissioner
- (14) Addl./Joint Commissioner of Excise
- (15) Director, Karnataka Rural Water Supply and Sanitation Agency and E/O Addl./Joint Secretary to Government, IDPR
- (16) Deputy Commissioner/Senior Assistant Commissioner/Special Deputy Commissioner/Gazetted Assistant to Divisional Commissioner/Chief Executive Officer of Zilla Panchayat
- (17) Commissioner for Religious and Charitable Endowment and E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government, Revenue Department

#### KERALA

- (1) Special Secretary/Additional/Joint/Deputy Secretary to Government
- (2) Joint/Deputy Commissioners
- (3) Secretary, Land Board
- (4) Director, Kerala Institute of Local Administration
- (5) Inspector General of Registrations
- (6) Director of Fisheries
- (7) Director of Panchayats
- (8) Director of Municipalities
- (9) Director of Public Relations
- (10) Director of Tourism
- (11) Director of Sports and Youth Affairs
- (12) Director of Social Welfare
- (13) Director, Scheduled Castes and Development Department

- (14) Labour Commissioner
- (15) Director of Employment and Training
- (16) Director of Civil Supplies
- (17) District Collectors
- (18) Director of Rehabilitation
- (19) Additional Director of Industries and Commerce
- (20) Director of Survey and Land Records
- (21) Director Scheduled Tribes Development Department
- (22) District Planning Officer/General Manager, District Industries Centre/Project Officer DRDA/Cardamom Settlement Officer/Sub-Collectors Grade-I.

**MADHYA PRADESH**

- (1) Collector
- (2) Additional Commissioner, Revenue
- (3) Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat
- (4) Additional/Deputy Secretary
- (5) Director Employment and Training
- (6) Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection
- (7) Secretary, Public Service Commission
- (8) Additional Commissioner, Sales Tax
- (9) Additional Commissioner, Tribal Development
- (10) Director, Agricultural Marketing
- (11) Director, Institutional Finance
- (12) Director, Urban Administration
- (13) Director, Panchayat and Social Welfare

**MAHARASHTRA**

- (1) Joint Secretary/Addl. Secretary/Special Secretary
- (2) Collector
- (3) Collector, Bombay Suburban District
- (4) Additional Collector
- (5) Chief Executive Officer, Zila Parishad
- (6) Director of Civil Supplies (Storage and Movement)
- (7) Deputy Director of Land Records
- (8) Inspector General of Registration
- (9) Additional Commissioner of Sales Tax
- (10) Additional Commissioner of Industries
- (11) Deputy Commissioner of Sales Tax
- (12) Director of Social Welfare
- (13) Additional Commissioner
- (14) Director of Handlooms, Power-looms and Cooperative Textiles
- (15) Director of Employment
- (16) Director of Sports and Youth Services
- (17) Controller of Rationing
- (18) Additional Commissioner of Tribal Sub-Plan
- (19) Director of Small Savings.

**MANIPUR-TRIPURA****MANIPUR**

- (1) Secretary to Government
- (2) Secretary to Chief Minister

- (3) Secretary to Public Service Commission
- (4) Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
- (5) Deputy Commissioner
- (6) Deputy Commissioner, Imphal East
- (7) District Planning Officer-cum-Additional Deputy Commissioner-cum-Additional District Magistrate
- (8) Commissioner for Departmental Enquiries
- (9) Commissioner for Excise
- (10) Commissioner for Taxes
- (11) Director of Vigilance
- (12) Director of Food and Civil Supplies
- (13) Registrar of Cooperative Societies
- (14) Director of Land Records and Settlement
- (15) Director of Tourism
- (16) Director of Information and Public Relations
- (17) Director of Commerce and Industries
- (18) Director of Transport
- (19) Director, Department for Development of Tribal and Backward Classes
- (20) Director of Municipal Administration and Urban Development
- (21) Director of Youth Affairs and Sports.

**TRIPURA**

- (1) Secretary to Government
- (2) Secretary to Chief Minister
- (3) Secretary to Public Service Commission
- (4) Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government
- (5) District Magistrate and Collector
- (6) Additional District Magistrate and Collector
- (7) Director of Higher Education
- (8) Director of School Education
- (9) Director of Vigilance
- (10) Director of Social Welfare and Social Education
- (11) Director of Food and Civil Supplies
- (12) Director of Land Records and Settlement
- (13) Director of Information, Cultural Affairs and Tourism
- (14) Registrar of Cooperative Societies
- (15) Director of Welfare for Scheduled Tribes
- (16) Director of Welfare for Scheduled Castes and Other Backward Classes
- (17) Labour Commissioner
- (18) Commissioner for Taxes and Excise
- (19) Commissioner for Departmental Enquiries
- (20) Director of State Institute of Public Administration and Rural Development
- (21) Director of Industries and Commerce
- (22) Director, Youth Affairs and Sports
- (23) Director of Information and Technology
- (24) Director of Handloom, Handicraft and Sericulture.

**NAGALAND**

- (1) Secretary
- (2) Additional/Joint/Deputy Secretary to Government

- (3) Deputy Commissioner
- (4) Additional Deputy Commissioner

**ORISSA**

- (1) Secretary/Additional Secretary to Government
- (2) Joint/Deputy Secretary to Government
- (3) Secretary, Board of Revenue
- (4) Magistrate and Collector
- (5) Additional District Magistrate/Sub-Collector, Grade I/Settlement Officer/Deputy Director, Consolidation/General Manager, DIG/Project Administrator, ITDA/Project Officer, DRDA
- (6) Registrar, Cooperative Societies
- (7) Additional Registrar, Cooperative Societies
- (8) Director, Harijan and Tribal Welfare
- (9) Director, Panchayati Raj
- (10) Director of Industries
- (11) Additional Director of Industries
- (12) Director of Employment
- (13) Inspector General of Registration and Excise Commissioner
- (14) Labour Commissioner
- (15) Director, Tourism
- (16) Director, Textiles
- (17) Director of Export Promotion and Marketing
- (18) Director, Social Welfare
- (19) Director, Special Projects.

**PUNJAB**

- (1) Additional/Joint Secretary to Government
- (2) Director of Information and Public Relations
- (3) State Transport Commissioner
- (4) Director of State Transport
- (5) Director of Industries
- (6) Director of Rural Development and Panchayats
- (7) Director, Development of Women and Child Development
- (8) Director of Land Records and Settlement, Consolidation and Land Acquisition
- (9) Director, Grievances and Pensions
- (10) Director of Local Government
- (11) Labour Commissioner and Director of Employment
- (12) Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes
- (13) Additional Director of Industries
- (14) Additional Registrar, Co-operative Societies
- (15) Additional Excise and Taxation Commissioner
- (16) Deputy Commissioner
- (17) Addl. Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner (Development).

**RAJASTHAN**

- (1) Special Secretary to Government
- (2) Deputy Secretary to Government

- (3) Settlement Commissioner
- (4) Director, Rural Development and Panchayati Raj
- (5) Collector and District Magistrate
- (6) Director, Watershed
- (7) Director, Secondary Education
- (8) Director, Small Savings
- (9) Director, State Insurance and Provident Fund
- (10) Chief Executive Officer, Zilla Parishad
- (11) Additional Commissioner, Commissioner Taxes
- (12) Director, Watershed Development and Soil Conservation
- (13) Additional Registrar, Co-operative Societies
- (14) Registrar, Board of Revenue
- (15) Additional Commissioner, Food
- (16) Director, Information and Public Relations
- (17) Director, Tourism
- (18) Director, Information Technology
- (19) I.G. Registration and Stamps
- (20) Secretary, RPSC
- (21) Director, Social Welfare
- (22) Director, Archaeology and Museum Department.

**SIKKIM**

- (1) Secretary to Government/Joint Secretaries/Deputy Secretaries
- (2) District Magistrates and Collectors

**TAMIL NADU**

- (1) Additional Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries to Government
- (2) Director of Adi Dravidar and Tribal Welfare
- (3) Deputy Commissioners/Joint Commissioners/Additional Joint Commissioners
- (4) Joint Commissioner of Civil Supplies Headquarters
- (5) Inspector General of Registration
- (6) Director of Agriculture
- (7) Director of Survey and Settlements
- (8) Director of Employment and Training
- (9) Director of Rehabilitation
- (10) Director of Handlooms and Textiles
- (11) Director of Fisheries
- (12) Director of Small Savings and Raffles
- (13) Director of Stationery and Printing
- (14) Director of Backward Classes
- (15) Deputy Commissioners for Commercial Taxes
- (16) Additional Commissioners of Industries and Commerce
- (17) Collectors
- (18) Settlement Officer
- (19) Director of Land Reforms
- (20) Additional Director of Agriculture
- (21) Additional Registrar of Cooperative Societies
- (22) Secretary, State Election Commission
- (23) Director of Most Backward Classes and Denotified Communities
- (24) Director of Town and Country Planning
- (25) Director of Agricultural Marketing

- (26) Director of Horticulture and Plantation Crops
- (27) Director of Treasuries and Accounts
- (28) Director of Statistics
- (29) Director of Collegiate Education
- (30) Director of Geology and Mining
- (31) Director of Information and Public Relations
- (32) Director, Sericulture
- (33) Director of Social Welfare
- (34) Sub-Collectors/Additional Collectors/Additional Collectors (Development)
- (35) Secretary, Tamil Nadu Public Service Commission
- (36) Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments
- (37) Commissioner for Disciplinary Proceedings (Madurai, Coimbatore)
- (38) Additional Director of Social Welfare
- (39) Director to Tourism
- (40) Controller of Examinations, Tamil Nadu Public Service Commission
- (41) Deputy Secretary, Mid-day Meal Programme
- (42) Director of Urban Land Ceiling
- (43) Joint Commissioner, Land Administration
- (44) Joint Secretary to Chief Minister
- (45) Deputy Secretary to Chief Minister
- (46) Commissioner, Government Data Centre

**UTTARANCHAL**

- (1) Commissioner and Director Industries
- (2) Commissioner, Labour and Director, Training and Employment
- (3) Director, Cultural and Sports
- (4) Transport Commissioner
- (5) Director, Information and Editor Gazetteer
- (6) Registrar, Cooperative Societies
- (7) District Magistrates
- (8) Additional Secretary
- (9) Chief Development Officer

**UTTAR PRADESH**

- (1) District Magistrates
- (2) Joint Development Commissioner/CDO/Additional/ Joint Project Administrator Area Development
- (3) Special Secretary to Government
- (4) Joint Secretary to Government
- (5) Additional Joint Labour Commissioner
- (6) Additional Joint Director of Industries
- (7) Additional Registrar Coop. Societies
- (8) Additional Commissioner, Rural Development
- (9) Additional/Joint Sales Tax Commissioner
- (10) Director, Panchayats

- (11) Director, Information
- (12) Director, Training and Employment
- (13) Director, Social Welfare
- (14) Secretary, Public Service Commission
- (15) Director, Urban Land Ceiling
- (16) Relief Commissioner
- (17) Director, Local Bodies
- (18) Regional Food Controller
- (19) Director (Administration), Medical Health and Family Welfare
- (20) Additional Registrar, Cooperative Societies
- (21) Deputy Land Reforms Commissioner
- (22) Directors, Bureau of Public Enterprises and Joint/ Special Secretary to Government
- (23) Director (Administration), SGPGI
- (24) Additional Director, Administrative Training Institute
- (25) Additional Resident Commissioner

**WEST BENGAL**

- (1) Director of Land Records and Survey
- (2) Director of Public Vehicles Department
- (3) Joint Secretary to Government
- (4) Director of Cottage and Small Scale Industries
- (5) Director of Evaluation, Development and Planning Department
- (6) Director of Rationing
- (7) Director of District Distribution Procurement and Supply
- (8) Director, Local Bodies and ex-officio Joint Secretary, Local Government and Urban Development Department
- (9) Secretary, Vigilance Commission
- (10) Registrar, Cooperative Societies
- (11) District Magistrate and Collector
- (12) Additional District Magistrate/Settlement Officer
- (13) Additional District Magistrate (DLLRO)
- (14) Land Acquisition Collector, Calcutta
- (15) Director of Employment
- (16) Director of Consumer Goods
- (17) Director of Fisheries
- (18) Director, ESI
- (19) Director of Sericulture
- (20) Principal Director, SIPARD, Kalyani
- (21) Commissioner, Agricultural Income Tax
- (22) Advisor, Industries
- (23) Director, Industries
- (24) Principal Secretary, Darjeeling Gorkha Hill Council
- (25) Secretary, KMDA
- (26) CEO, WBIDC

**C - Posts under the Central Government when held by member of the Service.**

Name of Post	Scale of Pay	Central (Deputation on Tenure) Allowance
(1) Cabinet Secretary	Rs. 30000/- (Fixed)	—
(2) Secretary to the Government of India/Special Secretary to the Government of India	Rs. 26000/- (Fixed)	—
(3) Additional Secretary to the Government of India	Rs. 22400-525-24500/-	—
(4) Joint Secretary to the Government of India	Rs. 18400-500-22400/-	—
(5) Director to the Government of India	Selection Grade (Rs. 15100-400-18300/-)	Fifteen per cent of the grade pay subject to the maximum of rupees one thousand per mensem.
(6) Deputy Secretary to the Government of India	(i) Selection Grade (Rs. 15100-400-18300/-) or (ii) Junior Administrative Grade (Rs. 12750-375-16500/-)	Fifteen per cent of the grade pay subject to the maximum of rupees one thousand per mensem. Fifteen per cent of the grade pay subject to the maximum of rupees one thousand per mensem and further subject to the condition that pay plus Central (Deputation on Tenure) Allowance shall not exceed the maximum of the scale.
(7) Under Secretary to the Government of India	(i) Junior Administrative Grade (Rs. 12750-375-16500/-) or (ii) Senior Time Scale (Rs. 10650-325-15850/-)	Fifteen per cent of the grade pay subject to the maximum of rupees eight hundred per mensem and further subject to the condition that pay plus Central (Deputation on Tenure) Allowance shall not exceed the maximum of the scale. Fifteen per cent of the grade pay subject to the maximum of rupees eight hundred per mensem and further subject to the condition that pay plus Central (Deputation on Tenure) Allowance shall not exceed the maximum of the scale.

**Note :—**The Central (Deputation on Tenure) Allowance specified in this rule shall be admissible to a member of the Service only during the normal tenure of deputation as prescribed by the Central Government from time to time.

[ F. No. 20011/1/2005-AIS-II ]

R. K. GUPTA, Desk Officer